वर्ष 12 • अंक 302 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 6 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

किसान बेच सकेंगे वेयरहाउस की ई-रसीद

शक्तिकांत दास पृष्ठ 4

आरबीआई के हाथ शहरी सहकारी बैंकों का नियमन

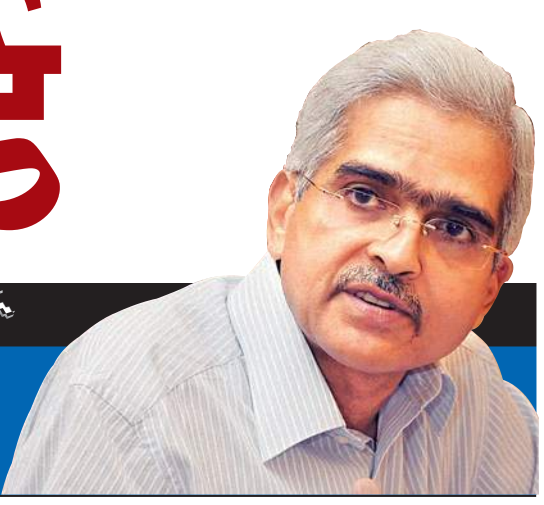

डॉलर रु. 71.20 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 78.50 ▼ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40049 ▼ 394 रुपये | सेंसेक्स 41142.70 ▲ 353.30 | निफ्टी 12089.20 ▲ 109.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 12086.30 ▼ 02.90 | ब्रेंट क्रूड 54.60 डॉलर ▲ 01.50 डॉलर

एक नज़र

कारोबारी दिग्गज तय करेंगे बीएस पुरस्कार के लिए नाम

देश के उद्योग जगत की जानी-मानी हस्तियों का एक निर्णायक मंडल गुरुवार को मुंबई में बैठक करेगा और वर्ष 2019 के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड के सालाना कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेताओं का चयन करेगा। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला आठ सदस्यीय निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हैं। निर्णायक मंडल के अन्य सदस्यों में जेएसडब्ल्यू समूह के सज्जन जिंदल, केकेआर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी संजय नैयर, ईवाई इंडिया अध्यक्ष राजीव मेमानी, ओमिड्यार नेटवर्क इंडिया की प्रबंध निदेशक रूपा कुडवा, मैकिंजी ऐंड कंपनी में सीनियर पार्टनर नोशिर काका, सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्रॉफ और बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के प्रबंध निदेशक अमित चंद्रा शामिल हैं। पृष्ठ 14

सेवा क्षेत्र की गतिविधियां सात वर्षों के उच्च स्तर पर

देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि जनवरी में सात वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार नए कारोबार मिलने, अनुकूल बाजार परिस्थितियों और कारोबारी धारणा सकारात्मक रहने से गतिविधियों में तेजी देखी गई है। आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विसेस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स (सेवा पीएमआई) जनवरी में 55.5 अंक पर रहा है। दिसंबर में यह यह 53.3 दर्ज हुआ था। यह 2013 से 2020 की अवधि में सेवा पीएमआई का सबसे ऊंचा स्तर है। पृष्ठ 4

आईटीआई ने वापस लिया एफपीओ

आईटीआई ने कमजोर मांग के मद्देनजर अपना 1,300 करोड़ रुपये का एफपीओ बुधवार को वापस ले लिया। ऐसा कभी-कभार ही देखने को मिलता है जब सरकार नियंत्रित कंपनी रकम जुटाने की अपनी योजना में असफल रहती है। आईटीआई दूरसंचार क्षेत्र को तकनीकी सेवा मुहैया कराती है। एफपीओ सरकार की विनिवेश योजना का हिस्सा नहीं था लेकिन इससे कमजोर कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने में आने वाली चुनौतियों का पता चलता है। पृष्ठ 2

मारुति की ईवी योजना ठंडे बस्ते में

ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए ऑटो एक्सपो में कई कंपनियों ने पेश किए ई-वाहन

शैली सेठ मोहिले और अरिंदम मजूमदार
ग्रेटर नोएडा, 5 फरवरी

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सूजुकी इंडिया की निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उतारने की योजना नहीं है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी केनिची अयुकावा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि रेंज की चिंता और ऊंची लागत जैसी समस्याओं से ग्राहकों को ईवी रास नहीं आएगा।

मारुति ने अपनी ईवी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है लेकिन अधिकांश दूसरी यात्री वाहन निर्माता कंपनियां जोरशोर से इस दिशा में काम कर रही हैं। इनमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, रेनो इंडिया, एमजी मोटर्स और किया मोटर्स सहित कई कंपनियां शामिल हैं।

दूसरी ओर उत्सर्जन के मानकों को पूरा करने के लिए मारुति सीएनजी और हाइब्रिड जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों पर जोर दे रही है। अयुकावा ने कहा, 'यह भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन उतारने का अनुकूल समय नहीं है। हम बाजार की स्थितियों और ग्राहकों की उम्मीद के मुताबिक फैसला करेंगे।' उन्होंने कहा कि सरकार पर्सनल इलेक्ट्रिक कार के लिए सब्सिडी नहीं दे रही है और कंपनी को किफायती इलेक्ट्रिक उत्पाद देने के तरीकों पर विचार करना होगा।

उन्होंने कहा, 'पार्किंग की जगह नहीं है, चार्जिंग की जगह नहीं है और इसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हुआ है। इस स्थिति में ईवी उतारना मुश्किल होगा। केवल कुछ ही लोगों की इसमें दिलचस्पी होगी।' अयुकावा ने कहा कि जब तक ईवी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तब तक हाइब्रिड वाहन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक अहम पड़ाव हो सकता है।

फोटोः संजय शर्मा

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उतारने के लिए बाजार और बुनियादी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं।
केनिची अयुकावा
एमडी व सीईओ, मारुति सूज़ुकी

ईवी पर मारुति की दलील

- ज्यादा खरीद लागत
- ईवी के साथ रेंज का मसला
- बुनियादी ढांचे की कमी
- ईवी को कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से चार्ज किया जाएगा जिससे होने वाले उत्सर्जन से क्लीन मोबिलिटी का मकसद पूरा नहीं होगा

लेकिन दूसरी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों की आयुकावा से अलग राय है। महिन्द्रा ऐंड महिन्द्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने सरकार द्वारा किए गए उपायों का हवाला देते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि हमें अब सरकार से और कुछ मांगना चाहिए। अब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है।'

टाटा मोटर्स भी ईवी के मोर्चे पर प्रयास तेज कर दिया है। कंपनी की योजना अगले दो-तीन साल में आधा दर्जन ईवी उतारने की है। टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिज़नेस के प्रेजिडेंट शैलेश चंद्रा ने हाल में मीडिया से बातचीत में कहा था कि कंपनी ने ईवी प्रौद्योगिकी में सबसे आगे रहने का मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने ई-वाहनों को प्रोत्साहन देने के सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वह निजी श्रेणी को इसका फायदा देकर और बेहतर कर सकती है।

प्रोत्साहनों का लाभ उठाने और ईवी को वित्तीय रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए महिंद्रा ने साझा मोबिलिटी क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

संबंधित खबर : पृष्ठ 3

वित्त आयोग बनाएगा विशेषज्ञ समिति

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 5 फरवरी

15वां वित्त आयोग इस महीने के अंत में केंद्र और राज्यों के राजकोषीय और कर्ज की स्थिति का आकलन करने के लिए समिति का गठन करेगा और पूर्ववर्ती राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन समिति के अनुरूप खाका प्रस्तुत करेगा। आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में यह जानकारी दी।

समिति भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गनर्वर ऊर्जित पटेल, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के साजिद शेनॉय, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी के रथिन रॉय और गोल्डमैन सैक्स की प्राची मिश्रा को शामिल कर सकती है या उनसे परामर्श कर सकती है।

सिंह ने कहा, 'वित्त आयोग को संचयी राजकोषीय घाटा और कर्ज जैसे मुद्दे पर ध्यान देने का जिम्मा सौंपा गया था और हमने इन मसलों को दूर करने का प्रयास किया है। इसलिए 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक के बाद मैंने अपनी अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।'

- वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह अपनी अध्यक्षता में करेंगे समिति का गठन
- समिति केंद्र और राज्यों को राजकोषीय प्रारूप की कर सकती है सिफारिश
- समिति में ऊर्जित पटेल, अरविंद सुब्रमण्यन जैसे विशेषज्ञ हो सकते हैं शामिल

सिंह ने कहा कि समिति में लेखा महानियंत्रक, भारतीय लोक लेखा सेवा, राज्य व्यय विभाग और अन्य केंद्रीय एवं राज्यों के निकायों के साथ-साथ विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आयोग को दिए गए कार्यक्षेत्र की रिपोर्ट के साथ आएगी। (शेष पृष्ठ 14 पर)

अब हम हथियार आयातक नहीं, निर्यातक हैं: मोदी

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 5 फरवरी

उत्तर प्रदेश जल्द ही देश के सबसे बड़े रक्षा विनिर्माण केंद्र के तौर पर उभरेगा और बुंदेलखंड के रक्षा गलियारे से लखनऊ और कानपुर को भी जोड़ा जाएगा। राजधानी लखनऊ में एशिया के सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी (डिफेंस एक्सपो) का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लंबे समय से दुनिया में हथियारों का आयातक रहे भारत से अब निर्यात की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब लक्ष्य आने वाले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाए। वर्तमान सरकार ने रक्षा आयुध निर्माण के क्षेत्र में पहले के मुकाबले दोगुने लाइसेंस दिए हैं। भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2014 में 2,000 करोड़ रुपये था वहीं आज यह बढ़ कर 17,000 करोड़ रुपये हो गया है ।

रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम चाहते हैं कि रक्षा निर्माण सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित न रहे बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भी बराबर की भागीदारी और साझीदारी हो। मैं समझता हूं कि उपयोगकर्ता और उत्पादक के बीच भागीदारी से राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसी को देखते हुए वर्ष 2018 में हमारी सरकार ने रक्षा विनिर्माण समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार एक हजार से ज्यादा रक्षा निर्माता व और दुनिया भर की 150 कंपनियां इस एक्सपो का हिस्सा हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्री और सैकड़ों व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं।

लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो में निशाना साधते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

आज का सवाल

क्या मारुति के पीछे हटने से ई-वाहन में अन्य कंपनियों को मिलेगा मौका

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या वित्त मंत्री की अपील पर निवेश करने आगे आएंगे उद्योगपति? हां **27.78%** नहीं **72.22%**

अपील पंचाट से सहमत कर विभाग

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 5 फरवरी

रिलायंस जियो इन्फोकॉम की प्रस्तावित दूरसंचार टावर और फाइबर ऑप्टिक तंत्र कारोबार अलग करने की योजना पर मुहर लगाने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश में आयकर विभाग को ठोस आधार नजर आ रहा है। दिलचस्प बात है कि दो महीने पहले ही विभाग ने कंपनी की योजना पर मुहर लगाने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी।

दिसंबर में एनसीएलएटी ने विभाग की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें जियो के टावर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परिसंपत्तियों को दो ढांचागत न्यासों (इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट) को स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई गई थी।

कर विभाग ने दिस दिन पहले एक संवाद में विधि मंत्रालय को अपने इस मामले पर अपने विचार से अवगत करा दिया था। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि कर विभाग ने आगे की कार्य योजना के लिए मंत्रालय की कानूनी राय मांगी थी।

सूत्रों के अनुसार कर विभाग का मानना है कि एनसीएलएटी ने अपने आदेश में वोडाफोन एस्सार कर प्रवंचना मामले सहित विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है। विभाग के अनुसार इस वजह से एनसीएलएटी के निर्णय में दमखम दिख रहा है। इस बारे में एक कर अधिकारी ने कहा, 'एनसीएलएटी के आदेश में दिए गए कुछ उद्धरण जियो मामले में भी लागू होते हैं। ऐसे में इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कानूनी रूप से कमजोर साबित हो सकता है।' एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि अपील न्यायाधिकरण के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने पर अंतिम निर्णय विधि मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। मंत्रालय दो हफ्तों में इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।

रिलायंस समूह की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसे ई-मेल भेजा गया, जिसका कोई जवाब नहीं आया। एनसीएलएटी ने 20 दिसंबर को अपने आदेश में रिलांयस जियो इन्फोकॉम की योजना पर आयकर विभाग की आपत्ति खारिज कर दी थी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएटी)ने जियो इन्फोकॉम की दूरसंचार टावर और फाइबर कारोबार को दो पृथक इकाइयों को हस्तांतरित करने की योजना को हरी झंडी दी थी। कंपनी इनके हस्तांतरण से अपने ऊपर कर्ज बोझ कम करना चाहती है। आयकर विभाग ने इस संबंध में कंपनी को मिली अनुमति पर कर प्रवंचना से संबंधित चिंता जाहिर की थी। एनसीएएटी ने अपने आदेश में कहा था, 'केवल इस बुनियाद किसी योजना की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती कि इससे संबंधित कंपनी की कर देनदारी कम हो जाएगी। हम एनसीएलटी के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।'

- जियो मामले में आयकर विभाग ने विधि मंत्रालय से मांगी कानूनी राय
- एनसीएलएटी ने दिसंबर में विभाग की याचिका निरस्त कर दी थी
- इससे पहले आयकर विभाग कर रहा था इसका विरोध

खबरों में रहे स्टॉक

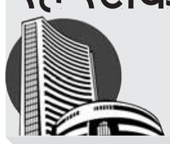

एवेन्यू सुपरमार्ट्स

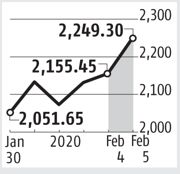

सबसे अधिक मूल्यवान 20 कंपनियों की सूची में शामिल

₹ 2,155.45 पिछला बंद भाव
₹ 2,249.30 आज का बंद भाव
▲ 4.35 %

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज

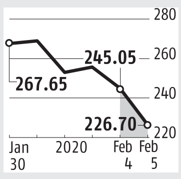

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनी के बहीखातों की जांच का आदेश दिया

₹ 245.05 पिछला बंद भाव
₹ 226.70 आज का बंद भाव
▼ 7.49 %

अवंति फीड्स

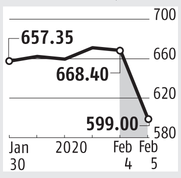

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 36 फीसदी घटा

₹ 668.40 पिछला बंद भाव
₹ 599.00 आज का बंद भाव
▼ 10.38 %

टाटा मोटर्स

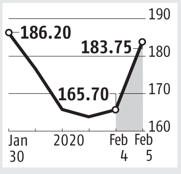

ऑटो एक्सपो 2020 में कई वाहनों का अनावरण किया

₹ 165.70 पिछला बंद भाव
₹ 183.75 आज का बंद भाव
▲ 10.89 %

बीपीसीएल

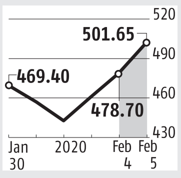

बोली लगाने में रोसनेफ्ट की दिलचस्पी की खबर

₹ 478.70 पिछला बंद भाव
₹ 501.65 आज का बंद भाव
▲ 4.79 %

संक्षेप में

एनआईआईटी का लाभ 40 फीसदी बढ़ा

कौशल और प्रतिभा विकास के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एनआईआईटी के बुधवार को जारी तीसरी तिमाही नतीजों में एकीकृत शुद्ध लाभ 40 फीसदी बढ़कर 27.1 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी क्षेत्र से मांग बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ा है। कंपनी ने एक साल पहले इसी तिमाही में 19.4 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर अवधि में एनआईआईटी का एकीकृत राजस्व 10 फीसदी बढ़कर 247.6 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 225.5 करोड़ रुपये रहा था। कंपनियों से पढ़ाई करने के लिए आने वाले समूहों से प्राप्त राजस्व इस दौरान 189.5 करोड़ रुपये रहा। *भाषा*

बॉश के शुद्ध लाभ में गिरावट

वाहन पुर्जे बनाने प्रमुख कंपनी बॉश लिमिटेड के प्रदर्शन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कंपनी ने दिसंबर 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ और राजस्व दोनों में ही गिरावट दर्ज की है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर अवधि के दौरान अपने कर पूर्व लाभ में सालाना आधार पर 27.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की और यह लुढ़ककर 347.5 करोड़ रुपये रह गया। *बीएस*

उत्पादन से लाभ घटाएगी टाटा पावर

कंपनी ने लाभ के लिए बनाई नई रणनीति, वितरण और अक्षय ऊर्जा पर रहेगा जोर

अमृता पिल्लई
मुंबई, 5 फरवरी

बिजली उत्पादन में अपनी एक सदी से भी अधिक समय की विरासत के साथ टाटा पावर अब अपनी राह बदलने के लिए सतर्क रुख अपना रही है। कंपनी ने एक समयावधि के भीतर उत्पादन कारोबार से प्राप्त मुनाफे को घटाकर महज 20 फीसदी करने और शेष मुनाफा वितरण एवं पारेषण और अक्षय ऊर्जा कारोबार से हासिल करने की योजना बनाई है।

टाटा पावर के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी प्रवीर सिन्हा ने कहा, 'फिलहाल इनमें से हरेक श्रेणी में हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है। इसे एक समयावधि के भीतर 40 फीसदी, 40 फीसदी और 20 फीसदी करने की योजना है जो मुनाफे के संदर्भ में होगा।'

करीब एक साल पहले टाटा पावर ने अलग-अलग क्लस्टर के तहत अपने विभिन्न कारोबार को एकीकृत किया था जबकि उसकी तापीय परिसंपत्तियां उत्पादन क्लस्टर के तहत हैं। अन्य दो प्रमुख क्लस्टर- टीऐंडडी क्लस्टर और अक्षय ऊर्जा क्लस्टर हैं जिसमें सौर विनिर्माण भी शामिल है। सिन्हा ने कहा कि उत्पादन कारोबार में कोई बड़ा पूंजी निवेश न होने के कारण टीऐंडडी और अक्षय ऊर्जा कारोबार में किए गए निवेश से रिटर्न मिलना अब शुरू हो चुका है।

सिन्हा ने उम्मीद जताई कि केवल टीऐंडडी कारोबार से प्राप्त मुनाफा अगले कुछ वर्षों में दोगुना हो जाएगा। कंपनी के उत्पादन क्लस्टर में कोस्टल गुजरात पावर (सीजीपीएल) शामिल नहीं है। सीजीपीएल मुंद्रा बिजली संयंत्र का परिचालन करने वाली टाटा पावर की सहायक इकाई है।

सिन्हा ने उम्मीद जताई कि मुंद्रा बिजली संयंत्र का घाटा चालू वित्त वर्ष में सबसे कम रहेगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020 के लिए मुंद्रा की वार्षिक घाटा करीब 900 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2019 में यह घाटा 1,700 करोड़ रुपये रहा था। सिन्हा ने कहा, 'पिछले नौ महीने के दौरान मुंद्रा का घाटा 650 से 700 करोड़ रुपये रहा। बेहतर ईंधन प्रबंधन, कोयले की ब्लेंडिंग और कोयला कीमतों में नरमी से मदद मिली। यह मुंद्रा के लिए अब तक का सबसे कम वार्षिक घाटा है।'

कंपनी इंडोनेशिया में अपने खनन लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया में है। सिन्हा ने कहा कि नवीनीकरण के लिए आवेदन अगले महीने जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में पीटी कल्टिम प्राइमा कोल के लिए लाइसेंस की अवधि 2021 में खत्म हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लाइसेंस के नियमों और शर्तों में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं होगा।

मुंद्रा बिजली संयंत्र को शुल्क दरों में संशोधन के लिए विभिन्न राज्यों से मंजूरी मिलने का भी इंतजार है। इससे करीब 50 फीसदी घाटे को पाटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा टाटा पावर अपनी गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों को भी भुनाने की तैयारी कर रही है।

आगे की राह

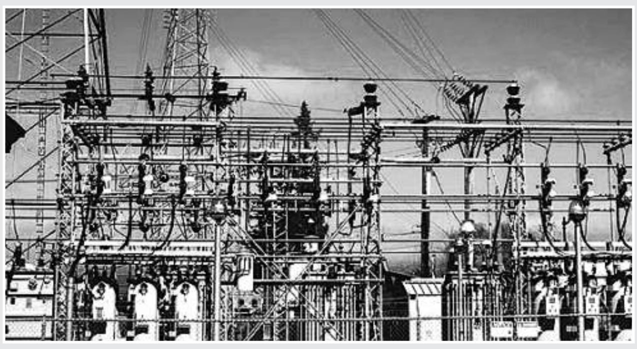

- अगले कुछ वर्षों में टीऐंडडी से मुनाफा होगा दोगुना
- मुंद्रा का घाटा वित्त वर्ष 2020 में 900 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
- अगले एक साल में 1 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों का विनिवेश होगा
- लाभ में टीऐंडडी, अक्षय ऊर्जा का योगदान 80 फीसदी होगा

फिनटेक बाजार में फ्लिपकार्ट की पैठ

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 5 फरवरी

- **ग्राहकों को उधारी, उपकरण बीमा से लेकर विक्रेताओं के वित्त पोषण जैसी पहल से फिनटेक श्रेणी में फ्लिपकार्ट ने 2019 में 40 फीसदी की वृद्धि दर्ज की**

वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भारतीय फिनटेक बाजार में आक्रामक तरीके से अपनी पैठ बनाते हुए एमेजॉन और अलीबाबा के निवेश वाली कंपनी पेटीएम जैसी प्रतिस्पर्धियों को टक्कर दे रही है। फ्लिपकार्ट की फिनटेक श्रेणी ने 2019 में 40 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। इस श्रेणी में ग्राहकों को उधारी, उपकरण बीमा और विक्रेताओं के लिए वित्त पोषण जैसे कारोबार शामिल हैं।

कंपनी अगले 20 करोड़ ग्राहकों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने जा रही है और इसलिए उसने फिनटेक उत्पादों और सेवाओं को ऐक्सेस करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसमें टियर-2 और टियर-3 शहरों को भी शामिल किया गया है जहां काफी आकर्षण दिख रहा है।

फ्लिपकार्ट की प्रमुख (फिनटेक एवं भुगतान कारोबार प्रमुख) स्मृति रविचंद्रन ने कहा, 'अब हम 20 करोड़ ग्राहक आधार में से करीब 6.5 करोड़ ग्राहकों को उधारी लेने के लिए समर्थ बनाया है। करीब 40 से 45 फीसदी ग्राहकों की पहुंच अभी भी उधारी तक नहीं हो पाई है।' उन्होंने कहा, 'फ्लिपकार्ट का ग्राहक आधार 20 करोड़ से बढ़कर अगले 3 से 4 वर्षों में 30 करोड़ जो जाएगा। इसलिए हमने इन 6.5 करोड़ ग्राहकों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हमारा उद्देश्य हरेक व्यक्ति को उधारी देना है।'

पीडब्ल्यूसी और उद्योग संगठन एसोचेम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय फिनटेक बाजार में कुल मिलाकर लेनदेन मूल्य 2019 में करीब 66.1 अरब डॉलर रहा जो 20.18 फीसदी सीएजीआर के साथ बढ़कर 2023 में 137.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ईवाई ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स 2019 के अनुसार, उभरते बाजारों में इसका चलन काफी दिखा और वर्ष 2019 में भारत एवं चीन में फिनटेक को अपनाने की दर 87 फीसदी रही जो 64 फीसदी की वैश्विक औसत दर से अधिक है।

रविचंद्रन ने कहा कि कंपनी ने देश में फिनटेक बाजार के विस्तार के लिए त्रिआयामी रणनीति अपनाई है। इसमें डेटा इनसाइट्स, वितरण एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भुगतान को आसान बनाना, विशेष तौर पर टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में ग्राहकों को उधारी के लिए समर्थ बनाना और उन्हें अपनी पंसद के उत्पाद खरीदने में मदद करना शामिल है। ग्राहकों को सरल खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए कंपनी एक नवोन्मेषी बीमा तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। पिछले महीने फ्लिपकार्ट ने वीजा सेफ क्लिक (वीएससी) को लॉन्च किया। यह फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एक नया भुगतान समाधान है जो उसे भारत के पहले इन-ऐप डिवाइस आधारित नेटवर्क सत्यापन समाधान उपलब्ध कराने में समर्थ बनाता है। इसके लिए 2000 रुपये तक के लेनदेन के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होगी।

नीलामी में 5जी स्पेक्ट्रम नहीं खरीदेगी भारती एयरटेल

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 5 फरवरी

भारती एयरटेल ने बुधवार को कहा कि वह आगामी नीलामी में 5जी स्पेक्ट्रम नहीं खरीदेगी क्योंकि इसकी कीमत काफी ज्यादा है। दूरसंचार नियामक ट्राई की सिफारिश के मुताबिक, 100 मेगाहट्र्ज 5जी स्पेक्ट्रम की लागत करीब 50,000 करोड़ रुपये होगी।

भारती एयरटेल के मुख्य कार्याधिकारी गोपाल विट्ठल ने बुधवार को निवेशकों के साथ बातचीत में कहा, हमारा मानना है कि कीमत काफी ज्यादा है। ऐसे में हम इस कीमत पर खरीद नहीं करेंगे।

दिसंबर 2019 में डिजिटल संचार आयोग ने देश भर में 8,300 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी रिजर्व प्राइस पर करने की योजना को मंजूरी दी थी, जो 5,22,850 करोड़ रुपये तक का होगा। इस बीच, भारती एयरटेल ने कहा कि वह देश के 11 सर्किल में 3जी नेटवर्क बंद करेगी और मुख्य रूप से डेटा की उच्च मांग को पूरा करने के लिए 4जी स्पेक्ट्रम लगाएगी। विट्ठल ने कहा, हमने 11 सर्किल में 3जी बंद करने का काम पूरा कर लिया है और उसे 4जी स्पेक्ट्रम में तब्दील कर दिया है। कंपनी ने कहा कि 3जी को 4जी में तब्दील करने पर पूंजीगत खर्च होगा क्योंकि 4जी की मांग बढ़ी है।

भारती एयरटेल ने मंगलवार को ऐलान किया कि दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध नुकसान 1,035 करोड़ रुपये रहा, जिसकी वजह एजीआर भुगतान के लिए प्रावधान रही। इस तरह से कंपनी ने लगातार तीसरी तिमाही में नुकसान दर्ज किया जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 86 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

परिचालन के मोर्चे पर हालांकि कंपनी ने औसत राजस्व प्रति ग्राहक (एआरपीयू) में क्रमिक आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की और यह 128 रुपये से 135 रुपये पर पहुंच गया। सालाना आधार पर मोबाइल राजस्व 9.6 फीसदी बढ़ा क्योंकि अच्छे ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने और कुछ इलाकों में टैरिफ बढ़ने का फायदा मिला। कंपनी की देनदारी व प्रावधान 30 सितंबर को 34,260 करोड़ रुपये था (8,747 करोड़ रुपये मूलधन, 15,446 करोड़ रुपये ब्याज, 3,760 करोड़ रुपये जुर्माना और ब्याज पर 6,307 करोड़ रुपये जुर्माना)।

'ई-कॉमर्स लेनदेन पर टीडीएस का प्रस्ताव गैर-जरूरी'

बजट 2020-21 में प्रस्तावित ई-कॉमर्स लेनदेन पर एक प्रतिशत टीडीएस से छोटे कारोबारियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित हो सकती है, एमेजॉन इंडिया के प्रमुख (भारत) अमित अग्रवाल ने बुधवार को यह बात कही।

उद्योग संगठन इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) की 14वीं इंडिया डिजिटल समिट में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा, 'हालिया बजट को देखें। इसमें स्रोत पर कर संग्रह को शामिल किया गया है। देखने में लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है लेकिन यह छोटे कारोबारियों की कार्यशील पूंजी को बुरी तरह प्रभावित करता है। अगर आप देखें कि देश में कारोबार करने के लिए प्रत्येक चरण पर कारोबार को किस तरह से पंजीकृत कराया जाता है, यह गैर-जरूरी कदम है।' अग्रवाल आईएएमएआई के अध्यक्ष भी हैं।

अग्रवाल ने कहा कि अगर कारोबारी लेनदेन में आने वाली बाधाओं को हटाना है तो कई और कदम उठाने की आवश्यकता है। अग्रवाल बजट प्रस्ताव में शामिल आयकर अधिनियम संबंधी नई धारा के बारे में बात कर रहे थे जो एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रस्ताव से ई-कॉमर्स कंपनियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित होगी और ऑनलाइन विक्रेताओं का नगदी प्रवाह घटेगा। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि टीडीएस के चलते नगदी सरकार तथा रिफंड सिस्टम के बीच फंस जाएगी। बजट में प्रस्तावित अधिरोपण की व्याख्या में कहा गया कि इकाई के मालिक के तौर पर परिभाषित ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन अथवा प्रबंधन करता है, को बिक्री या सेवा या दोनों की सकल राशि पर एक प्रतिशत टीडीएस काटना होगा। *बीएस*

आईटीआई ने वापस लिया एफपीओ

बीएस संवाददाता
मुंबई, 5 फरवरी

आईटीआई लिमिटेड ने कमजोर मांग के कारण बुधवार को 1,300 करोड़ रुपये का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) वापस ले लिया। यह कदम किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के विरले उदाहरण में से एक है जब वह रकम जुटाने की कवायद में नाकाम रही। आईटीआई लिमिटेड दूरसंचार क्षेत्र को तकनीकी समाधान मुहैया कराती है। यह एफपीओ हालांकि सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह कम पसंदीदा पीएसयू की हिस्सेदारी बिक्री में चुनौतियों को रेखांकित करता है।

आईटीआई ने एक बयान में कहा, बाजार कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण कंपनी ने एफपीओ वापस लेने का फैसला लिया है। स्टॉक एक्सचेंजों के आंकड़ों के मुताबिक, एफपीओ को सिर्फ 62 फीसदी आवेदन मिले थे। आईटीआई ने एफपीओ बंद होने की तारीख दो बार बढ़ाई और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कीमत दायरा भी घटाया था। यह एफपीओ मूल रूप से 28 जनवरी को बंद होना था। पहली बार इसकी तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी की गई और दूसरी बार 5 फरवरी। इसका कीमत दायरा घटाकर 71 से 77 रुपये किया गया, जो पहले 72 से 77 रुपये प्रति शेयर था।

बुधवार को आईटीआई का शेयर करीब 5 फीसदी उछलकर 84 रुपये पर बंद हुआ। इस एफपीओ के जरिए आईटीआई 18.18 करोड़ नए शेयर जारी करने जा रही थी। इस इश्यू के जरिए 20 फीसदी हिस्सेदारी बिकनी थी, जिसका द्वितीयक बाजार की कीमत पर असर पड़ता।

अभी इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 90 फीसदी है। आईटीआई का मूल्यांकन अभी 7,550 करोड़ रुपये है। बीओबी कैपिटल मार्केट्स, कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज और पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इस एफपीओ का कामकाज संभाल रही थी।

विगत में सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयों मसलन एलआईसी व एसबीआई ने पीएसयू शेयर की बिक्री में काफी मदद की है। बैंकरों ने कहा, आईटीआई के एफपीओ की नाकामी से संकेत मिलता है कि सरकार चाहती थी कि रकम जुटाने की इस योजना को सामान्य मांग का सहारा मिले।

विश्लेषकों ने कहा कि कीमत और अनिश्चित कारोबारी परिदृश्य से निवेशकों की मांग प्रभावित हुई होगी। एक विश्लेषक ने कहा, कीमत के अलावा निवेशक पिछले वित्त वर्ष में कंपनी के लाभ में गिरावट और कारोबारी परिदृश्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि आईटीआई का अधिकतम कारोबार सराकरी स्वामित्व वाली कंपनियों से आता है, जो बेहतर स्थिति में नहीं है।

आईटीआई इस एफपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज समाप्त करने और कार्यशील पूंजी के वित्त पोषण में करने पर विचार कर रही थी। विश्लेषकों ने कहा, कंपनी को अब रकम जुटाने के अन्य तरीके पर नजर डालनी होगी, जिसमें निजी नियोजन शामिल है।

ऑटो एक्सपो पर कोरोनावायरस का साया

चीनी वाहन कंपनियों की भारतीय योजना को झटका

डिलिवरी और नई पेशकश में हो सकती है देर क्योंकि ज्यादातर कंपनियां कलपुर्जों के लिए चीन पर हैं निर्भर

किया मोटर्स ने कॉन्सेप्ट कार सोनेट से हटाया पर्दा फोटो : संजय शर्मा

अरिंदम मजूमदार और शैली सेठ मोहिले
नई दिल्ली/मुंबई, 5 फरवरी

चीन कोरोनावारस के प्रसार पर लगाम कसने लिए संघर्ष कर रहा है, लिहाजा उस देश में बंद फैक्टरियां व लॉजिस्टिक केंद्र धीरे-धीरे चीन के वाहन दिग्गजों के कारोबार में अवरोध पैदा कर रहे हैं, जिनने हाल में भारत में प्रवेश किया है। भारतीय बाजार के लिए उन आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ज्यादातर चीनी कंपनियां आश्रित हैं, उस पर दबाव पड़ रहा है और इस वजह से डिलिवरी में देर हो सकती है और कुछ अन्य कंपनियां नई पेशकश टाल सकती हैं।

एमजी मोटर्स के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी गौरव गुप्ता ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि हम ज्यादातर कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए चीन पर आश्रित हैं, लिहाजा हमारे ऊपर कुछ समय तक असर पड़ेगा। ऐसे में फरवरी में एमजी हेक्टर की डिलिवरी में देर हो सकती है। हमने इस बारे में ग्राहकों को सूचित कर दिया है।

एसएआईसी मोटर कॉर्प की इकाई ने जून में मध्यम आकार वाला स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन हेक्टर पेश किया था और जल्द ही उसने अपनी ज्यादातर प्रतिस्पर्धी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था क्योंकि कंपनी की खुदरा बिक्री 3,000 वाहन मासिक से ज्यादा रही है।

चीन की सरकार के स्वामित्व वाली हाइमा ऑटोमोबाइल ने साल 2021 में भारत में पहला इलेक्ट्रिक वाहन उतारने की योजना बनाई है और वह अपनी रणनीतिक योजना पर कोरोनावायरस के असर का आकलन कर रही है। भारत में प्रवेश के लिए कंपनी ने बर्ड इलेक्ट्रिक संग साझेदारी की है। बर्ड इलेक्ट्रिक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, चूंकि हम पूरी तरह से तैयार वाहन का आयात करेंगे, लिहाजा हमें आपूर्ति श्रृंखला के बंद होने का कुछ अवरोध देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी योजना में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। वाहन निर्माता ने आज वैश्विक स्तर दो सबसे कामयाब यात्री वाहन 7 एक्स और 8 एस का अनावरण ऑटो एक्सपो में किया। भारत के लिए निवेश योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कोरोनावायरस के प्रसार से ग्रेट वॉल मोटर्स की योजना प्रभावित हो सकती है, जिसने भारतीय बाजार में 1 अरब डॉलर के निवेश का खाका खींचा है। यह जानकारी कंपनी के निदेशक (रणनीति और योजना) कौशिक गांगुली ने दी।

कोरोनावायरस के प्रसार से सिर्फ चीनी फर्में ही चिंतित नहीं हैं। चीन से सोर्सिंग करने वाली वैश्विक निर्माता भी चिंतित हैं, जो दुनिया भर में विस्तार करना चाह रही हैं।

मर्सिडीज बेंज के एम ल्यूर्स ने कहा, कोरोनावायरस का असर वाणिज्यिक उत्पादन पर पड़ेगा क्योंकि चीन में सबकुछ बंद है। हमारे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसका कितना असर होगा, इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। मर्सिडीज ने पिछले साल चीन में रिकॉर्ड 6.90 लाख कारें बेची, जो सालाना आधार पर 5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है।

कोरिया की हुंडई ने अपने सबसे बड़े विनिर्माण आधार कोरिया में उत्पादन बंद कर दिया है। हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक एस एस किम ने कहा, कंपनी वैश्विक स्तर पर सोर्सिंग नेटवर्क से आपूर्ति के लिए बातचीत कर रही है।

ग्रेट वॉल मोटर लाएगी सबसे सस्ती ई-कार!

ऋषभ कृष्ण सक्सेना
नई दिल्ली, 5 फरवरी

चीन की नामी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) निर्माता ग्रेट वॉल मोटर कंपनी (जीडब्ल्यूएम) भारत के बाजार में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार ला सकती है। कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में आज बैटरी से चलने वाली कार आर1 पेश की। हालांकि कंपनी ने इसे भारत में लाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उसकी एक आपूर्तिकर्ता कंपनी से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इसे अगले साल भारत में उतारने की योजना है।

आर1 को दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कहा जाता है और सूत्र के मुताबिक सब्सिडी मिलने पर भारत में इस कार की कीमत 8 से 9 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

हालांकि महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने ऑटो एक्सपो में आज ही केयूवी 100 इलेक्ट्रिक उतार दी, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपये है। लेकिन इस कार में 15.9 किलोवॉट की बैटरी है, जो एक बार चार्ज होने पर कार को 140 किलोमीटर से कुछ अधिक दौड़ा सकती है। मगर चीन में आर1 28.5 और 33 किलोवॉट की बैटरियों के साथ बिकती है और एक बार चार्ज होने पर 350 किलोमीटर तक चल सकती है।

बैटरी की क्षमता के लिहाज से 9 लाख रुपये कीमत होने पर भी यह भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी। देश में केयूवी 100 इलेक्ट्रिक के अलावा सभी इलेक्ट्रिक वाहन 12-15 लाख रुपये से अधिक कीमत के ही हैं, जिससे आर1 उतारना ग्रेट वॉल मोटर के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें कई दूसरी खासियत भी हैं। मसलन यह 102 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है और चार्जिंग स्टेशन पर महज 20 मिनट तक चार्ज करने के बाद 120 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है।

हालांकि ग्रेट वॉल मोटर के निदेशक (सेल्स एवं मार्केटिंग) हरदीप सिंह बराड़ ने यह बताने से इनकार कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार कब लाई जाएगी मगर उन्होंने यह जरूर कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक कार लाने की कंपनी की पक्की योजना है और भारत में ग्रेट वॉल ईवी को उतारा जा सकता है, कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी भारत में बैटरी शोध तथा विकास में गति लाएगी। साथ ही जनरल मोटर्स से खरीदे जा रहे तलेगांव संयंत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की भी कंपनी की योजना है। बराड़ ने बताया कि कंपनी सबसे पहले हवल एच6 पेश करेगी, जिस पर से कंपनी ने आज ही पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि तलेगांव संयंत्र का अधिग्रहण इस साल की दूसरी छमाही में पूरा हो जाएगा और जरूरत के मुताबिक बदलाव के बाद इसमें उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले एसयूीव हवल एच6 बनाई जाएगी, जो 2021 में आ जाएगी और उसके बाद बाजार की मांग के मुताबिक मॉडल पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेट वॉल मोटर भारत के कार बाजार में हलचल मचाने वाले उत्पाद लाएगी और उनमें ऐसे कई फीचर होंगे, जो यहां के ग्राहकों ने अभी तक नहीं देखे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का बाजार एसयूवी के लिहाज से सबसे तेजी से बढ़ रहा है और जीडब्ल्यूएम के लिए यह सबसे अनुकूल पहलू है।

कंपनी 8-9 लाख रुपये में ला सकती है आर1

ऑटो एक्सपो में कई वाहनों से हटा पर्दा

पृष्ठ-1 का शेष

ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू हुए ऑटो एक्सपो के 15वें संस्करण में अधिकांश पंडालों को ईवी को प्रमुखता दी गई है। वाहन निर्माताओं ने एक दर्जन से अधिक ई-वाहनों पर से पर्दा हटाया जिनमें बाजार में उतारे जाने को तैयार मॉडल और कॉन्सेप्ट मॉडल शामिल हैं। एक्सपो में पहली बार हिस्सा ले रही चीन की एफएडब्ल्यू और ग्रेट वॉल मोटर्स भी भारत में ई-वाहनों को तवज्जो दे रही हैं। ऑटो एक्सपो में कंपनी एक कॉन्सेप्ट ईवी कार, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन और एक चौपहिया वाहन के प्रोटोटाइप 'एटम' का प्रदर्शन कर रही है।

देश में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और उत्सर्जन में कटौती के लिए सरकार ई-वाहनों पर जोर दे रही है। भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना के तहत कई तरह के नीतिगत उपायों और प्रोत्साहनों की घोषणा की है। पिछले साल ई-वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 15 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया था। साथ ही ऐसे वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को आय कर में छूट देने की भी घोषणा की गई थी। लेकिन ये सभी सुविधाएं केवल वाणिज्यिक श्रेणी में दी गई हैं।

ई-वाहनों पर मारुति की सोच के बारे में कंपनी के कार्यकारी निदेशक (डिजाइन एवं इंजीनियरिंग) सी वी रमन ने कहा, बिक्री उत्साहजनक नहीं है। मारुति के लिए बिक्री अहम है। कंपनी किफायती उत्पाद लाने में विश्वास करती है और अब तक ईवी की कीमत आम ग्राहकों की पहुंच से बाहर है। पेट्रोल और डीजल वाहनों की कीमत जहां 5 से 6 लाख रुपये है वहीं इनके ईवी संस्करण की कीमत करीब दोगुना है। ऊंची कीमत से यह वाहन व्यावहारिक नहीं है।

संक्षेप में

एवेन्यू सुपरमार्ट्स जुटाएगी 4,000 करोड़ रुपये

एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने कम से कम 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पात्र संस्थागत नियोजन कार्यक्रम पेश किया है। देश की सबसे मूल्यवान खुदरा श्रृंखला 1,999 रुपये की आधार कीमत पर 2 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बोर्ड की बैठक 10 फरवरी को होगी, जिसमें क्यूआईपी कीमत को मंजूरी दी जाएगी। कंपनी का शेयर बुधवार को 4.35 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,249 रुपये पर बंद हुआ। अभी कंपनी का मूल्यांकन 1.41 लाख करोड़ रुपये है और यह देश की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल है। क्यूआईपी से राधाकृष्ण दमानी की अगुआई वाले प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी घटाने में मदद मिलेगी, जिनके पास 79.73 फीसदी हिस्सेदारी है। डीमार्ट खुदरा श्रृंखला का परिचालन करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स को 20 मार्च तक हिस्सेदारी 75 फीसदी से नीचे लाना है ताकि न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का पालन हो सके। क्यूआईपी से प्रवर्तकों से हिस्सेदारी 2.8 फीसदी कम हो सकती है। प्रवर्तकों को 1.9 फीसदी और हिस्सा बेचना होगा। इसके बारे में बैंकरों का कहना है कि इसका जरिया ओएफएस हो सकता है। दिसंबर तिमाही एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 53 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 394 करोड़ रुपये रहा, जो बाजार के अनुमान से ज्यादा रहा। शुद्ध बिक्री इस अवधि में 24 फीसदी बढ़कर 6,752 करोड़ रुपये रही। *बीएस*

डालमिया की सहायक ने निपटाया मामला

डालमिया सीमेंट (भारत) की सहायक कैलकॉम और वित्तीय लेनदार गौरांतको ने सभी दावे व प्रतिदावे का निपटान आपसी सहमति से कर दिया है। डालमिया भारत समूह ने एक बयान में यह जानकारी दी। इस निपटान में एनसीएलटी के गुवाहाटी पीठ के सामने रखे दावे व प्रतिदावे शामिल हैं। मॉरीशस की गौरांतको की अपील पर कैलकॉम को ट्रिब्यूनल में स्वीकार किया गया था। सूत्रों ने कहा कि इसके तहत निपटान की रकम 100 करोड़ ररुपये से कम है। पक्षकार एनसीएलटी के गुवाहाटी पीठ से याचिका वापस लेने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। *बीएस*

इंस्टामोजो ने टाइम्स से खरीदा गेटमीएशॉप

फिनटेक स्टार्टअप इंस्टामोजो ने बुधवार को कहा कि उसने टाइम्स इंटरनेट के स्वामित्व वाला स्टार्टअप गेटमीएशॉप का अधिग्रहण कर लिया है। इस सौदे के तहत टाइम्स इंटरनेट संयुक्त इकाई में निवेश भी करेगी। इंस्टामोजो के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी एस स्वेन ने एक साक्षात्कार में कहा कि सौदे की कीमत 50 लाख डॉलर है। हालांकि उन्होंने अधिग्रहण की कीमत और नए निवेश के बारे में अलग-अलग जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, टाइम्स इंटरनेट अब इंस्टामोजो बोर्ड का हिस्सा होगी। *बीएस*

दलाल पथ पर आईआरसीटीसी नई बुलेट ट्रेन

बीएस संवाददाता
मुंबई, 5 फरवरी

आईआरसीटीसी के शेयरों में उछाल से रेलवे टिकटिंग कंपनी को सबसे मूल्यवान सार्वजनिक उपक्रम की सूची में आगे बढ़ने में मदद मिली है। पिछले 10 कारोबारी सत्र में इस कंपनी का शेयर 50 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है। सबसे मूल्यवान सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में अभी आईआरसीटीसी का स्थान 23वां है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 24,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अक्टूबर में आईपीओ के समय यह 50 अग्रणी कंपनियों की सूची में भी नहीं थी। अभी इसका मूल्यांकन कुछ अहम पीएसयू मसलन द न्यू इंडिया एश्योरेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया और बीएचईएल से भी ज्यादा है। पिछले पखवाड़े में आईआरसीटीसी का बाजार मूल्यांकन 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ा है, जो निचले स्तर वाली 20 सूचीबद्ध पीएसयू के संयुक्त बाजार मूल्यांकन से भी ज्यादा है।

बुधवार को आईआरसीटीसी का शेयर 6.8 फीसदी की उछाल के साथ 1,509 रुपये पर बंद हुआ और इसकी कीमत 23 जनवरी के 995 रुपये के मुकाबले 52 फीसदी ज्यादा है। यह तेजी सरकार के लिए अच्छी खबर होगी, जिसकी हिस्सेदारी इस कंपनी में 87.4 फीसदी है। आईआरसीटीसी अक्टूबर में बाजार में सूचीबद्ध हुई थी। आईपीओ में इसके शेयर की कीमत 320 रुपये थी। सूचीबद्धता के दिन ही यह शेयर 2.3 गुना चढ़ा था और आगाज के दिन सबसे ज्यादा लाभ हासिल करने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था।

सस्ती सेवा से बढ़ रहा एयर इंडिया का कर्जः पुरी

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि एयर इंडिया पर लगातार बढ़ते कर्ज की प्रमुख वजहों में सस्ती विमानन सेवा की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अलावा ऊंची ब्याज दर का बोझ और परिचालन खर्च में इजाफा शामिल है। पुरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि विनिवेश की प्रक्रिया से गुजर रही एयर इंडिया पर 2016-17 में 48447 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो 2017-18 में बढ़कर 55308 करोड़ रुपये और 2018-19 में 58255 करोड़ रुपये हो गया। *भाषा*

सेवा क्षेत्र की शानदार शुरुआत

घरेलू ऑर्डरों की बदौलत निक्केई इंडिया सर्विसेज पीएमआई जनवरी में 55.5 रहा

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 5 फरवरी

नए वर्ष में सेवा क्षेत्र की शुरुआत धमाकेदार रही है। जनवरी में नए ऑर्डर सात साल में सबसे तेज रफ्तार से बढ़े हैं। इसके सामने दिसंबर में पांच महीने की सबसे अधिक वृद्धि बौनी पड़ गई है। यह आंकड़ा बुधवार को जारी एक सर्वेक्षण का है।

निक्केई इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जनवरी में 55.5 रहा, जो दिसंबर में 53.3 के स्तर से अधिक है। पीएमआई की शब्दावली में 50 अंक से अधिक आंकड़ा विस्तार और इससे कम आंकड़ा संकुचन को इंगित करता है। उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि आलोच्य महीने के दौरान नए अंतरराष्ट्रीय कारोबार से भी सेवा क्षेत्र का आउटपुट सात साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि इससे कंपनियों को 2019 में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से निजात मिलेगी। उस समय तीन महीनों में पीएमआई घटा था। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक अन्य सर्वेक्षण के मुताबिक सेवाओं में वृद्धि अगस्त में 43 महीनों के सर्वोच्च स्तर 54.7 पर पहुंच गई थी, जिसके बाद दो महीनों में लगातार गिरावट आई थी। हालांकि नवंबर से लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। यह विनिर्माण गतिविधियों के समानांतर रही है। जनवरी में पीएमआई 55.3 पर पहुंचने पर विनिर्माण वृद्धि में भी बढ़ोतरी हुई है। पीएमआई का 55.3 का स्तर करीब 8 वर्षों में सबसे ऊंचा है।

नीति निर्धारकों के लिए अच्छी खबर

- जनवरी में नए ऑर्डर सात साल में सबसे तेज बढ़े
- काम के ज्यादातर नए ऑर्डर घरेलू बाजार से आए
- आर्थिक सुस्ती के लंबे दौर के बाद घरेलू बाजार में मांग बढ़ने का संकेत
- पिछले महीने में उपभोक्ता सेवा वृद्धि सबसे अधिक रही है। इसके बाद परिवहन एवं भंडारण कंपनियों ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की

सर्वेक्षण के भागीदारों के मुताबिक जनवरी में सेवाओं की बिक्री में लगातार चौथे महीने इजाफा हुआ है। पिछले महीने में उपभोक्ता सेवा वृद्धि सबसे अधिक रही है। इसके बाद परिवहन एवं भंडारण कंपनियों ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। जनवरी में वृद्धि दर में अनुकूल बाजार स्थितियों और बेहतर मांग की बदौलत इजाफा हुआ। नए काम के ऑर्डर भी सात वर्षों में सबसे अधिक बढ़े हैं। नीति निर्धारकों इस बात से खुशी होगी कि काम के ज्यादातर नए ऑर्डर घरेलू बाजार से आए हैं, जिससे 2018 में आर्थिक गिरावट के लंबे दौर के बाद घरेलू बाजार में मांग बढ़ने का संकेत मिल रहा है।

ताजा रुझानों के विपरीत पीएमआई सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2019 की तुलना में ज्यादार वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पैदा हुई है, लेकिन लगातार 11 महीनों तक बढ़ोतरी के बाद जनवरी में सेवा निर्यात में गिरावट आई है। पैनल में शामिल बहुत से लोगों ने कहा कि इसकी वजह चीन, यूरोप और अमेरिका में कमजोर मांग है।

इसके नतीजतन इस क्षेत्र में नियुक्तियां लगातार 29वें महीने बढ़ी हैं। हालांकि रोजगार के असवरों में बढ़ोतरी की रफ्तार में दिसंबर की तुलना में मामूली बदलाव आया है। हालांकि वित्त एवं बीमा उप क्षेत्रों की कंपनियों में कर्मचारियों की तादाद कम हुई है।

नए कारोबारों में उच्च वृद्धि से इनपुट महंगाई में भी इतनी ही बढ़ोतरी हुई है। औसत इनपुट लागत में सात वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इनपुट महंगाई में पिछले साल तगड़ी बढ़ोतरी रही थी। सर्वेक्षण के भागीदारों ने कहा कि अधिक लागत की वजह से ब्यूटी उत्पादों, खाद्य, मालभाड़े, ईंधन और मरम्मत की कीमतों में इजाफा हुआ है।

आईएचएस मारकिट में मुख्य अर्थशास्त्री और रिपोर्ट की लेखक पोल्लन्ना डी लीमा ने कहा, 'कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का पूरा भार ग्राहकों पर डालने के बजाय खुद भी वहन किया। इससे आगामी महीनों में बिक्री कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिससे बिक्री घट सकती है। कंपनियां अपने लाभ मार्जिन को बचाने के लिए नियुक्तियों पर रोक लगा सकती हैं।' हालांकि सेवाओं के लिए वसूली जाने वाली औसत कीमतों में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है।

कर विवाद समाधान विधेयक पेश

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 5 फरवरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान की बजट घोषणा को लागू करने के लिए आज लोक सभा में विधेयक पेश किया। प्रत्यक्ष कर विवादों के मामलों में 30 नवंबर, 2019 तक 9.32 लाख करोड़ रुपये का कर फंसा हुआ था।

सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश किया। इसमें कमीशनर (अपील), आयकर अपील न्यायाधिकरण (आईटीएटी) उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटान में ब्याज, जुर्माने और अभियोजन की छूट की पेशकश की गई है।

अगर भुगतान 31 मार्च तक किया जाएगा तो ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट दी जाएगी। हालांकि इस अवधि के बाद भुगतान करने पर विवादित राशि की 10 फीसदी राशि अतिरिक्त देनी होगी।

यह योजना सभी मामलों पर लागू होगी, भले ही ऐसे मामलों में मांग लंबित है या उसका भुगतान कर दिया गया है। लंबित याचिका आकलन या पुनर्आकलन ऑर्डर के संबंध में विवादित कर, ब्याज या जुर्माने के खिलाफ या विवादित ब्याज या फीस के खिलाफ हो सकती है, जहां कोई विवादित कर नहीं है। असल में याचिका कर कटौती या स्रोत पर संग्रह के संबंध में डिफॉल्ट पर निर्धारित कर के खिलाफ भी हो सकती है। जो मामले विवादित ब्याज या जुर्माने से संबंधित कर बकाये के हैं, उनमें 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करने पर विवादित जुर्माने या ब्याज की राशि का 25 फीसदी चुकाना होगा। हालांकि इसके बाद भुगतान करने पर 30 फीसदी राशि देनी होगी।

योजना क्रियान्वयन

- सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश किया
- 31 मार्च तक भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में मिलेगी पूरी छूट

बजट में वित्त वर्ष 2020 के लिए संशोधित अनुमानों में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य घटाकर 11.7 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बजट अनुमान में 13.35 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि इसमें साल दर साल आधार पर 2.9 फीसदी वृद्धि की जरूरत होगी।

सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस योजना से सरकार के लिए मुकदमेबाजी का खर्च घटेगा। इसके साथ ही कुछ राजस्व भी प्राप्त होगा।

सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में विभिन्न न्यायाधिकरणों में अटके 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने पिछले साल अपने पहले बजट में सबका विश्वास योजना की घोषणा की थी, जो अप्रत्यक्ष कर के मुकदमों की संख्या घटाने के लिए लाई गई थी। इस योजना की बदौलत 1,89,000 मामलों का निपटान किया गया है।

प्रत्यक्ष कर समाधान योजना की जमीनी तैयारी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश भर में अपने कार्यालयों से कहा है कि वे अगले सप्ताह तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के आंकड़े मुहैया कराएं।

कमीशनरों को भेजे गए संवाद में कहा गया है, 'योजना को लागू करने के लिए सीबीडीटी को ऐसे मामलों के डेटा की जरूरत है, जो उच्च न्यायालयों के स्तर पर लंबित हैं।'

आरबीआई के दायरे में शहरी सहकारी बैंक

सोमेश झा
नई दिल्ली, 5 फरवरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भारत के शहरी और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों से संबंधित निगरानी और अंकेक्षण के और अधिकार मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बैंकिंग नियमन संशोधन अधिनियम, 2020 को आज मंजूरी दे दी गई। इस कदम का मकसद इन बैंकों पर आरबीआई को ज्यादा नियामकीय नियंत्रण प्रदान करना है।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, 'वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही बहु-राज्यीय और शहरी सहकारी बैंकों को भी आरबीआई के नियमन के तहत लाया जाएगा। हालांकि यह बदलाव केवल बैंकिंग से जुड़े कामकाज के लिए होंगे और प्रशासनिक अधिकार पहले की तरह पंजीयक के पास बने रहेंगे।'

उन्होंने कहा कि इस तरह के सहकारी बैंकों का ऑडिट आरबीआई के नियमन के अनुसार होगा और नियामक की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन कार्यप्रणाली लागू की जाएगी। इसके साथ ही आरबीआई ऐसे बैंकों के बोर्ड सदस्यों के लिए न्यूनतम पात्रता स्तर भी तय करेगा और मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त करने के लिए नियामक की सहमति लेनी होगी।

ज्यादा अधिकार

- मंत्रिमंडल ने बैंकिंग नियमन संशोधन अधिनियम, 2020 को दी मंजूरी
- ऑडिटिंग और निगरानी को लेकर आरबीआई को मिलेंगे ज्यादा अधिकार
- इस तरह के सहकारी बैंकों में नियुक्ति के लिए भी होंगे नियम

वर्तमान में इस तरह के बैंकों के प्रबंधन के को सहकारी निकायों द्वारा चुना जाता है और उनकी नियुक्तियों को लेकर आरबीआई के पास सीमित अधिकार होते हैं। जावडेकर ने कहा, 'स्थिति बिगड़ने पर आरबीआई को बोर्ड को निरस्त करने का अधिकार होगा।'

बीएस सूडोकू 3657

	7		1		2			
9		4		5			1	
1	3							4
2	6		8	1				
4								3
				2	3		8	1
7							6	8
	4			8		7		9
			9		4		3	

परिणाम संख्या 3656

1	2	4	3	7	6	5	9	8
9	8	6	1	5	4	3	7	2
5	3	7	2	9	8	4	6	1
4	7	2	5	3	9	1	8	6
3	6	5	8	2	1	9	4	7
8	9	1	6	4	7	2	3	5
2	4	8	7	1	3	6	5	9
7	1	9	4	6	5	8	2	3
6	5	3	9	8	2	7	1	4

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम
★★★☆☆

महाराष्ट्र के वधावन में नए बंदरगाह को मंजूरी

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 5 फरवरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में बंदरगाह की स्थापना को आज मंजूरी दे दी। इस पर कुल 65,544.54 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा।

वधावन बंदरगाह को 'लैंड लॉर्ड मॉडल' पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनाया जाएगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) सबसे बड़ा साझेदार होगा, जिसके पास 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी होगी। यह एसपीवी बंदरगाह का बुनियादी ढांचा विकसित करेगा। सभी कारोबारी गतिविधियों का परिचालन पीपीपी मॉडल के तहत निजी डेवलपरों द्वारा किया जाएगा। इस समय भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं।

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2000/2010, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4250/4300, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1450/1550,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4200/4250, लालमती 3150/3200, चावल (सोना) 2700/2750,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1350, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1425, फ्लैक 1372, डीएमओ 980, टरपीन लैस बोल्ड 1448

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1030/1100, खुरपा 950/1010,चाकू 1050/1095, रसकट 900/910, शक्कर 1100/1150, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, बुंदकी 3270, बुढ़ाना 3300, शामली 3250,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/965, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4200, खल: सरसों 2150/2250, बिनौला 2250/2350, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5000/5200, गेहूं (मिल) 2120/2125, मक्की 2100/2115, बाजरा 1800/1810, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4370/4375,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3700/3750, जौ 2100/2125,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 7000/7100, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1825/1835, चना 4000/4100, काबली चना 5000/6000, मूंग 6900/7000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)107, राइसब्रान (अखाद्य) 104, खल सरसों 1900, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1000, लाल 1020, कंटीन्यूअस 1150,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 8000/8700, अरहर दाल 7400/7900, उड़द साबुत 7300/8400, उड़द धोया 9000/9800, छिलका 8700/9300, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5300/5400,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5800/5900, सेला 5250/5300, शरबती साधारण सेला 3700/3750, शरबती स्टीम 4000/4050, चावल 1509 सेला 4950/5000, धान: शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4025/4075, हरियाणा 4000/4030, राजस्थान 4000/4030, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2000/2010,

फाजिल्का
गेहूं 2020/2030, सरसों 4150/4200 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4000/4050, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2350/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2000/2040, चावल परमल कच्चा 2325/2365, से ला 2260/2310, मक्की यूपी 2100/2120, दाल उड़द छिलका 8600/9700, चना देशी 4700/4750, दाल चना 5100/5150, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7500/ 8900, चीन 8500/9000, शर्मिली 6000/7300,

करनाल
गेहूं दड़ा 2000/2025, बासमती चावल 6300/6400, धान 1121 नं. 2700/2750, पूसा 1509 धान 2600/2640, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 4950/4975, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3700/3750, जौ 1840/1850, सरसों 3900/3950, मूंग 7000/7100, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1140/1160, देशी घी (एक ली/जार) 360/480, रिफाइंड (टीन) 1480/1500,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3850/3900, खल बिनौला मोटी 2150/2250, बिनौला 2600/3100, सरसों तेल 8750/8800, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3700/3750, बाजरा 1700/1750 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 302

वित्त आयोग की सिफारिशें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत शनिवार को अगले वर्ष के आम बजट के साथ ही 15वें वित्त आयोग की सन 2020-21 से संबंधित पहली रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत की। वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र का दायरा विवाद का विषय बन चुका है क्योंकि ये कई अहम मामलों में पिछली व्यवस्था से अलग है।

राज्यों को चिंता थी कि आयोग से कहा गया कि वह सन 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मानना बंद करे और इसके स्थान पर आबादी के कहीं अधिक ताजा आंकड़े प्रयोग में लाए। ऐसा करने से देश के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र के उन राज्यों को नुकसान होता जिन्होंने आबादी नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया।

यह भी कहा गया कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा का फंड राज्यों को दिए जाने वाले फंड पूल में से ही अलग किया जाए और राज्यों के लिए लोकलुभावन नीतियों को हतोत्साहित किया जाए।

इन बाधाओं को देखते हुए वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में राज्यों की मांग और केंद्र सरकार के बीच एक मध्य मार्ग निकाला गया।

हालांकि इसमें सन 1971 के आबादी के आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया गया लेकिन इसने फॉर्मूले में बदलाव किया है जिसके चलते करों को राज्यों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ताकि इस बदलाव से हुई क्षति की आंशिक तौर पर पूर्ति की जा सके।

उदाहरण के लिए आबादी का भार 17.5 फीसदी से कम करके 15 फीसदी कर दिया गया है और जनांकीय प्रदर्शन का भार 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। सापेक्षिक आय का भार भी पांच फीसदी कम किया गया है।

बहरहाल, दक्षिण भारत के राज्य मसलन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल की कर हिस्सेदारी में अभी भी अपेक्षाकृत कमी आएगी। यद्यपि वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की है कि कुछ राज्यों को विशेष अनुदान दिया जाए ताकि वे इस भारी कमी से निजात पा सकें लेकिन केंद्र सरकार इससे प्रसन्न नहीं है।

केरल के वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि आम बजट में वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजस्व घाटा अनुदान को 74,000 करोड़ रुपये से कम करके 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें दो राय नहीं कि आगे चलकर यह मामला गंभीर हो जाएगा और इस कदम के लिए केंद्र सरकार के पास शायद ही कोई सफाई हो।

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को आयोग की अनुशंसाओं को सही ढंग से लागू करना चाहिए। खासतौर पर तब जबकि चालू वर्ष में राज्यों को किया जाने वाला हस्तांतरण करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये कम रहा और वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।

आयोग की रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू यह है कि कर राजस्व में राज्यों की कुल हिस्सेदारी जिसे 14वें वित्त आयोग ने 42 फीसदी निर्धारित किया था और 15वें वित्त आयोग ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के चलते उसमें केवल एक फीसदी की कमी की है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट में इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

यह सच है कि केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अपना बोझ राज्यों पर डालने से समस्या हल नहीं होगी।

राजकोषीय प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे देश के संघवाद के दीर्घकालिक महत्त्व को समझना चाहिए, न कि मौजूदा सरकार की अंशकालिक राजकोषीय चिंताओं को। आयोग की अंतिम रिपोर्ट में भी अंतरिम रिपोर्ट की तरह ही उक्त बातें नजर आनी चाहिए।

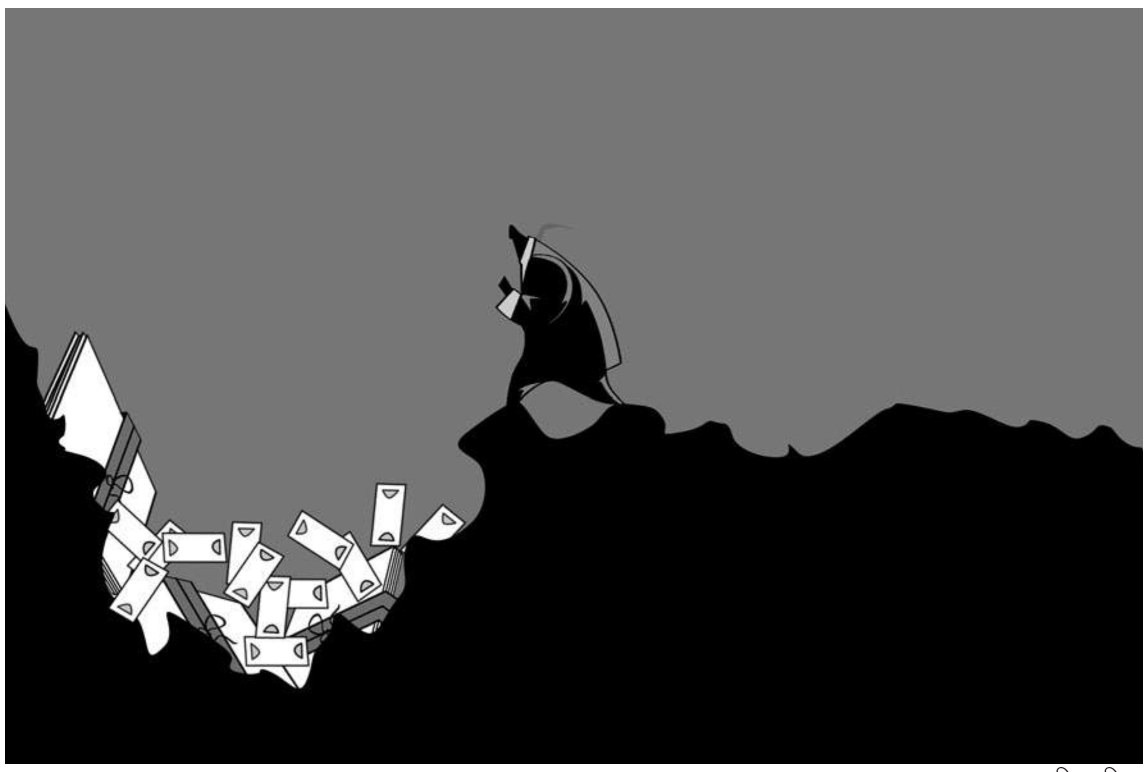

बिनय सिन्हा

बजट में फिर सामने आए ढांचागत राजस्व गतिरोध

केंद्रीय बजट में इस बात को कमोबेश स्वीकार कर लिया गया है कि उसमें विस्तारवादी राजकोषीय नीति के लिए जगह नहीं है। इस संबंध में विस्तार से दृष्टि डाल रहे हैं रथिन रॉय

गत वर्ष जुलाई में वित्त वर्ष 2020 के बजट को लेकर अपने आलेख में मैंने चेतावनी दी थी कि सरकार ढांचागत राजकोषीय गतिरोध से गुजर रही है और राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में गलत ढंग से आशावादी आंकड़ों के माध्यम से उसे छिपाने का प्रयास कर रही है। इस वर्ष का बजट पारदर्शी है। परंतु सरकार के समक्ष राजकोषीय बाधाएं बरकरार हैं क्योंकि राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त नहीं हैं। बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे की बड़ी वजह यह बाधा है।

वित्त वर्ष 2020 में सकल कर राजस्व प्राप्तियां 3 लाख करोड़ रुपये रही। यह बजट अनुमान में उल्लिखित राशि से कम है। इसमें आधी कमी के लिए कॉर्पोरेट कर में कमी उत्तरदायी रही, यह आंकड़ा कर दरों में कटौती की घोषणा के वक्त अनुमानित से अधिक रहा। शेष आधा हिस्सा अप्रत्यक्ष करों में 1.32 लाख करोड़ रुपये की कमी के कारण आया। समग्रता में देखा जाए तो वित्त वर्ष 2020 में सकल कर राजस्व में जीडीपी के 1.46 फीसदी के बराबर कमी आई। केंद्र के शुद्ध कर राजस्व में जीडीपी के 0.7 फीसदी के बराबर कमी आई और राज्यों के जीडीपी के 0.75 फीसदी के बराबर कमी आई। इसका राज्यों के कर संग्रह में कमी पर असंगतिपूर्ण प्रभाव पड़ा जिसकी वजह उपकरों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी रही। ऐसा इसलिए क्योंकि इन उपकरों पर कर दरों में कटौती का असर नहीं हुआ। यानी राजकोषीय तनाव राज्यों पर असर डाल रहा है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में इस तथ्य की अनदेखी कर दी गई है।

इस कमी के कारण और विनिवेश प्राप्तियों में अतिरिक्त कमी के कारण कुल व्यय में जीडीपी के 0.43 फीसदी कमी आई है। ऐसा तब है जबकि राजकोषीय घाटे और जीडीपी का अनुपात 3.3 फीसदी से बढ़कर 3.8 फीसदी हो गया। गैर कर राजस्व में जीडीपी की तुलना में 0.16 फीसदी का इजाफा हुआ। इस तरह देखें तो यह विस्तारवादी नहीं बल्कि संकुचन वाला बजट है। शायद इसी वजह से वित्त मंत्री अपने लंबे भाषण में वृद्धि में आई मंदी को लेकर कुछ नहीं बोलीं। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति कैसे इसे हल करेगी।

परंतु वित्त वर्ष 2021 के बजट अनुमान हकीकत के करीब हैं। इसमें कहा गया है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शुद्ध कर राजस्व में कमी आएगी। परंतु उसने यह भी कहा है कि व्यय-जीडीपी अनुपात में जीडीपी के 0.33 फीसदी के बराबर इजाफा होगा। यह अपने आप में एक पहेली लगती है जब तक कि हम विनिवेश प्राप्तियों के अनुमान पर नजर नहीं डालते। विनिवेश प्राप्तियों को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर 65,000 करोड़ रुपये से 2.1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऐसे में परिसंपत्तियों की बिक्री में भारी इजाफे की सहायता से व्यय-जीडीपी अनुपात में इजाफे की भरपाई की जाएगी और राजकोषीय घाटा कम किया जाएगा। फिलहाल मुझे यह भरोसेमंद नहीं लगता।

यह दिलचस्प है कि वित्त वर्ष 2021 में राजस्व घाटे और जीडीपी का अनुपात वित्त वर्ष 2020 के 2.4 फीसदी से बढ़कर 2.7 फीसदी हो गया। यानी पूंजीगत व्यय अनुपात के लिए कुल उधारी वित्त वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटे का 0.8 फीसदी गिरी। सन 2020 में यह गिरावट 1.4 फीसदी थी। यानी 2021 में नीति है-बढ़े राजस्व व्यय की फंडिंग विनिवेश के जरिये करना।

सरकार की सराहना की जानी चाहिए कि उसने बजट से इतर उधारी का व्यय विवरण में स्पष्ट उल्लेख किया। यह जीडीपी के 0.8 फीसदी पर बरकरार है। इस वर्ष कुल सरकारी उधारी जीडीपी के 4.6 फीसदी के बराबर है। अगले वर्ष इसके 4.3 फीसदी की दर से बढ़ने की आशा है। अर्थशास्त्रियों के लिए बेहतर यही होगा कि वे इन वास्तविक आंकड़ों का इस्तेमाल करें। सभी तीन वर्षों में इस अतिरिक्त व्यय का ज्यादातर हिस्सा भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों की फंडिंग के लिए जाता है। मुझे नहीं लगता कि यह व्यय किसी भी तरह वृद्धि में आए धीमेपन को हल करता है। इससे मेरी यह धारणा मजबूत होती है कि सरकार के पास विस्तारवादी राजकोषीय नीति के लिए कोई गुंजाइश शेष नहीं है।

मुझे व्यय में बदलाव लाने वाली ऐसी नीतियों की अपेक्षा थी जो वृद्धि में आए धीमेपन को हल करें। खेद की बात है कि प्रतिष्ठानों पर होने वाला व्यय, जीएसटी उपकर, ब्याज भुगतान, सांविधिक और वित्त आयोग के हस्तांतरण आदि वित्त वर्ष 2019 से 2021 के बजट अनुमान तक 6.8 फीसदी से 7 फीसदी के बीच स्थिर हैं। यानी सरकारी व्यय का आधा हिस्सा फंसा हुआ है। अन्य आधे हिस्से की बात करें तो सब्सिडी की हिस्सेदारी में कमी आई है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार की योजनाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में किया गया है।

बिना प्रतिबद्धता वाले व्यय की बात करें तो वित्त वर्ष 2021 में कृषि व्यय में 2020 की तुलना में 28 प्रतिशत इजाफा हुआ। बुनियादी परियोजनाओं को आश्चर्यजनक रूप से 12,500 करोड़ रुपये का कम आवंटन हुआ, विकास व्यय के आवंटन में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। शिक्षा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काफी कम इजाफा किया गया।

वित्त वर्ष 2020 के संशोधित अनुमान की बात करें तो राजकोषीय घाटे में पूरी बढ़ोतरी व्यय-जीडीपी अनुपात को बजट स्तर पर बरकरार रखने में अक्षम थी। इस वर्ष राजस्व घाटा कम होगा लेकिन वित्त वर्ष 2021 में उसमें इजाफा होगा। प्रतिबद्ध व्यय में इजाफा होगा और कर-जीडीपी अनुपात का ढांचागत ठहराव इस वर्ष भी बना रहेगा। यह बजट वही बातें कहता है जो मैं लंबे समय से दोहराता आ रहा हूं। बात यह कि मध्यम अवधि में विस्तारवादी राजकोषीय नीति की गुंजाइश नहीं है।

राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समीक्षा समिति के बचाव मार्ग का हल्काफुल्का जिक्र विश्वसनीय नहीं है। इसे स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की सलाह पर लागू किया जाना था लेकिन वह परिषद अब तक गठित नहीं की जा सकी है। बजट में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि इसे क्यों लागू किया गया। सरकार ने ऐसा कोई खाका पेश नहीं किया जो एफआरबीएम समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप हो। सबसे बुरी बात, मैंने दिखाया कि बढ़ी हुई राजकोषीय गुंजाइश का इस्तेमाल केवल कर राजस्व में हुई कमी की भरपाई के लिए किया गया। वास्तव में ऐसा करके भी इस तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता है कि मध्यम अवधि में राजकोषीय स्थिति कमजोर है और इसलिए यह दर्शाना निरर्थक होगा कि एफआरबीएम पथ पर नियंत्रित वापसी एक विश्वसनीय लक्ष्य है।

(लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी के निदेशक हैं। लेख में विचार निजी हैं)

समय के साथ शक्तिशाली होता अपरिभाषित संवैधानिक प्रावधान

अदालती आईना

एम जे एंटनी

संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो एक समय निहायत तुच्छ थे लेकिन अब उनका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। अनुच्छेद 142 इसकी बानगी है। यह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई आदेश पारित कर सके। संविधान निर्माताओं को अंदाजा नहीं था कि इसमें इतना बड़ा बदलाव आएगा और इसलिए उन्होंने मई 1949 में बिना किसी बहस के इसे पारित कर दिया था। परंतु बाद में न्यायालय ने इसका बार-बार प्रयोग किया और यह न्यायिक प्राधिकार का अहम जरिया बन गया।

हाल ही में इसका प्रयोग अयोध्या मामले, राष्ट्रीय नागरिक पंजी से जुड़े आदेशों, कोयला खदान मामलों, संवैधानिक नियुक्तियों और राजमार्गों पर शराब बिक्री बंद करने संबंधी आदेशों में किया गया।

पूर्ण न्याय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। न्यायाधीश इनका मनमुताबिक प्रयोग करते हैं। कई फैसलों में इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है लेकिन अभी भी इसे लेकर अस्पष्टता बरकरार है। कुछ निर्णय कहते हैं कि इसका इस्तेमाल उस खालीपन को भरने के लिए किया जाता है जो कानून की खामोशी से उपजता है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह अधिकार पूरक और स्वीकारोक्ति कारक है। एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार को अपरिभाषित और असूचीबद्ध छोड़ना श्रेयस्कर है। यह अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है और माना गया था कि यह इस बात की गारंटी होगी कि इसका इस्तेमाल सीमित और सुचिंतित ढंग से होगा। हालांकि न्यायाधीशों ने चेतावनी दी थी कि यह प्रावधान अन्य लोकतांत्रिक संविधानों में नहीं पाया जाता है और हमारे यहां भी इसका इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। परंतु इन दिनों हाई प्रोफाइल मामलों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके कई तरह के राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। अनिर्वाचित न्यायाधीशों के हाथ में मौजूद पूर्ण न्याय की तलवार कई संवेदनशील मामलों पर लटकती रहती है और वह कभी भी हमला कर सकती है।

अयोध्या मामले में दो अहम आदेश इस अनुच्छेद पर आधारित थे- मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देना और प्रस्तावित योजना में निर्मोही अखाड़े को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इससे पहले ढांचे को गिराने से संबंधित आपराधिक मामले रायबरेली से लखनऊ अदालत स्थानांतरित कर दिए गए थे जबकि 25 वर्ष बाद मुकदमा समाप्त होने को था।

असम में एनआरसी के विवादित मसले पर आदेश उसी तरह पारित किए गए जैसे दो समांतर जनहित याचिकाओं में। यह मामला अब अदालत के समक्ष लंबित अवस्था में है क्योंकि सड़कों पर विरोध हो रहा है।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में इस अप्रत्याशित शक्ति का इस्तेमाल करने के त्रासद परिणाम हुए। सन 1993 से दिए गए आवंटन सन 2004 में आवंटितों को बिना सुनवाई का अवसर दिए निरस्त कर दिए गए। इस नियम के अतिशय प्रयोग ने तमाम तरह की चिंताओं को जन्म दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक रिपोर्ट (एससीआर) के अनुसार अनुच्छेद 142 का पहला प्रयोग सन 1961 के नानावटी मामले में हुआ था। उसमें हत्या के आरोपी एक नौसेना अधिकारी की सजा को निलंबित किया गया था। एससीआर में इसके बाद लंबे समय तक इस अधिकार के इस्तेमाल का ब्योरा नहीं मिलता। यह माना जाता था कि पूर्ण न्याय करने की शक्ति का प्रयोग केवल प्रक्रियात्मक मामलों में किया जाना है। परंतु सन 1975 के आपातकाल के बाद कानून का विस्तार करके हर तरह के अन्याय और यहां तक कि जनहित याचिकाओं तक को इसमें शामिल कर लिया गया। भ्रष्ट राजनेताओं (विनीत नारायण मामला, 1997), न्यायाधीशों (के वीरास्वामी, 1991) के खिलाफ भी इस कानून का जमकर प्रयोग किया गया।

इसके अलावा सन 1989 में यूनियन कार्बाइड मामले के दावे निपटाने, सन 1979 में आव्रजन अधिनियम की जांच और कार्यस्थल पर यौन शोषण से निपटने (विशाखा, 1997) तक के लिए इसे प्रयोग में लाया गया। अक्सर आदेश पारित होने के बाद जल्द ही उन्हें भुला दिया जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम के क्रियान्वयन के दिशानिर्देश इसका उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए कितने लोगों को वह आदेश याद होगा जिसमें कहा गया था कि चिकित्सकीय उपकरणों के आयात में सीमा शुल्क में राहत पाने वाले अस्पतालों को उन गरीब लोगों के नाम प्रकाशित करने होंगे जिनका उन्होंने हर माह इलाज किया।

अनुच्छेद 142 पर होने वाली चर्चाएं प्राय: अस्पष्ट भाषा में होती हैं। वे इस बात की अनदेखी करती हैं कि कानून की भाषा स्पष्ट और सहज होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक सामान्य व्यक्ति अयोध्या मामले में दिए गए निर्णय के एक पैराग्राफ को पढ़कर भौंचक रह जाएगा, 'जहां ऐसा प्रतीत होता है कि किसी परिस्थिति को संभालने में दृढ़ता कमजोर पड़ रही है, वहां इस अदालत की पूर्ण न्याय करने की पूर्ण शक्ति वह आखिरी अपील है जो उस समता का बचाव करती है जिसका संरक्षण कानून को करना होता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालत के पास यह अधिकार है कि वह तार्किक और न्यायपूर्ण ढंग से राहत प्रदान कर सके।' बहुधार्मिक राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा अस्थिर माहौल में अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शी और सख्त रुख अपनाना आवश्यक है। अधिवक्ता अच्छी तरह जानते हैं कि शब्दों की आड़ में कमजोर कदम को छिपाया जा सकता है।

इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए मौजूदा एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कुछ वक्त पहले अमेरिकी न्यायाधीश बेंजामिन कार्डोजो को उद्धृत किया था। उन्होंने कहा था कि न्यायाधीश कोई मध्ययुगीन नाइट नहीं होते जो अपने आदर्शों की तलाश में अपनी मर्जी से भटकते रहें।

कानाफूसी

विशिष्ट सलाह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करने के बाद जब मीडिया से बातचीत की तो उद्योग जगत के पास उनके लिए विशिष्ट नीतिगत मशविरे थे। फिक्की द्वारा आयोजित एक समारोह में मौजूद लोगों के समक्ष अगले वित्त वर्ष के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के भारी भरकम विनिवेश लक्ष्य की सराहना करते हुए एक कारोबारी ने कहा कि सरकारी उपक्रमों की बिक्री करने के बजाय सरकार उनका पुनर्चक्रण करे। अधिकारी ने कहा कि सरकार को इसे पुनर्चक्रण विभाग कहना चाहिए ताकि सरकार के इरादे में सकारात्मक बदलाव आ सके। उन्होंने कहा कि उनके पिता पूछते रहते हैं कि सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं। वित्त मंत्री ने उनके इस सवाल पर कुछ नहीं कहा और केवल अपनी गरदन हिला दी। इसके बाद वह अगले सवाल से मुखातिब हो गईं।

दुर्लभ अवसर

पिछले छह वर्ष में ऐसा कम ही हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद उसी दिन लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद ज्ञापन का जवाब दिया हो। बहरहाल इस बार ऐसा होने जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री एक ही दिन दोनों सदनों में प्रस्ताव पर बोलेंगे। विपक्षी सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव का ताल्लुक दिल्ली विधानसभा चुनाव से हो सकता है जिसके लिए मतदान शनिवार को होना है। विपक्ष ने प्रस्ताव में 400 से अधिक संशोधन की बात कही है। बीते छह वर्ष में दो अवसरों पर विपक्ष ने राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधनों का दबाव बनाया है। उसके बाद से विपक्ष के सदस्यों की संख्या घटी है और वे इस स्थिति में नहीं रहे कि संशोधन करा सकें। दोनों सदनों में अगले सप्ताह बजट पर भी चर्चा होगी। बजट सत्र 11 फरवरी को स्थगित होगा और सदन 2 मार्च को दोबारा बैठेगा।

आपका पक्ष

स्तरहीन राजनीति की ओर बढ़ता देश

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार नेतागण स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं तथा अन्य नेताओं के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए काले धब्बे के समान है। एक केंद्रीय मंत्री एक सभा में गोली मारने की बात कहते हैं तथा कुछ दिन बाद गोली चल भी जाती है जो उचित नहीं है। एक सांसद मुख्यमंत्री के लिए नक्सली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेतागण चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे नेताओं और मंत्रियों की अमर्यादित भाषा सुनकर राजनीति की साख धूमिल होने लगी है। जिस संसद में कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब नेताओं द्वारा कही गई असंसदीय भाषा के विरोध में नारे लगने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या इन सब के बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। क्या सभ्य, सौम्य एवं सुसंस्कृत लोगों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं रह गई है। अगर ऐसे लोगों के लिए जगह है भी तो क्या वह केवल हाशिये पर ही रह सकते हैं। हाल के तीन उदाहरणों से ऐसा लगने लगा है कि शब्दों की मर्यादा तोड़ देना, मारपीट करना औरअभद्र भाषा का प्रयोग करना भी राजनीति में सफलता के लिए नई योग्यता के पैमाना बन रहे हैं। सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। वहां लोग दलों को धर्म विशेष में बांट कर उपहास उड़ाने लगते हैं। हालांकि लोग अब इसे गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि कोई किसी देशव्यापी राजनीति दलों पर ऐसे सांप्रदायिक आरोप कैसे लगा सकता है। सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनीतिक दल धर्म और जातियों में बंट गए हैं। भारतीय राजनीति में सफलता के लिए कुछ परिस्थितियां जरूरी हैं जैसे किसी राजनीतिक परिवार से आना, पूंजीपति या धनाढ्य होना या आपराधिक पृष्ठभूमि का होना। इसके अलावा अगर कोई अभद्र भाषा के प्रयोग में पारंगत है तो उसके लिए भी अवसर की कमी नहीं है। भारतीय राजनीति अपनी गरिमा खोती जा रही है।

अनु मिश्रा, सीवान

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चुनावी सभा में उमड़े कार्यकर्ता *-पीटीआई*

घबराने की जरूरत नहीं, स्वच्छता जरूरी

कोरोनावायरस से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए सतर्कता और इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। हमें उन कारकों से बचना चाहिए जिनसे कोरोनावायरस के फैलने का खतरा रहता है। अगर आपको किसी भी तरह की शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस हो रही है तो बेहतर है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाएं और घर में ही आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारा शरीर थका हुआ महसूस करता है, उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर पहले की तुलना में कमजोर हो जाती है। इससे हम पर बाहरी वायरस का हावी होने का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को कोरोनावायरस के कारण बहुत घबराने की जरूरत नहीं हैं। सर्जिकल मास्क का बंडल खरीदने या हर समय वायरस के भय में जीने से बेहतर है कि हम स्वच्छता और हाईजीन का पूरा ध्यान रखें। खुद को खांसी-जुखाम और फ्लू से बचाकर रखें। बुखार होने पर डॉक्टर के पास जाने से गुरेज नहीं करें और उनकी सलाह लें।

विधान वर्मा, भोपाल

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

किसान बेच सकेंगे वेयरहाउस की ई-रसीद

वित्त मंत्री ने बजट में ई-नाम के साथ ऐसी ई-रसीदों के एकीकरण की घोषणा की थी

राजेश भयानी
मुंबई, 5 फरवरी

वित्त मंत्री ने शनिवार को अपने बजट भाषण में जिस इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के साथ नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के एकीकरण की घोषणा की थी, वह एक-दो महीने में पूरा होने की उम्मीद है।

वेयरहाउस रसीदें उन भंडारगृहों द्वारा जारी की जाती हैं जो किसी भंडारगृह में जमा की गई वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक लेखा-जोखा रखते हैं और बाद में पूंजी बाजार में परिचालन करने वाले भंडारगृहों की तरह उनका हस्तांतरण करते हैं। अलबत्ता अब वेयरहाउस के सामान की रसीदें भी हस्तांतरित की जा सकती है और इसलिए इनका कारोबार भी किया जा सकता है। सीडीएसएल द्वारा स्थापित भंडारगृह - सीडीएसएल कमोडिटी रिपॉजिटरी लिमिटेड पहले से ही एकीकृत हो चुका है और ई-नाम पर कारोबार करने वाली वस्तुओं के लिए ई-एनडब्ल्यूआर जारी करना शुरू कर दिया है। एनसीडीईएक्स द्वारा स्थापित अन्य भंडारगृह एनईआरएल एकीकरण की प्रक्रिया में हैं।

- ई-नाम, कृषि मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग और दो गोदाम कर रहे एकीकरण पर विचार-विमर्श
- नेटवर्क के साथ जुड़ चुका है एक भंडारगृह, दूसरा जुड़ने की तैयारी में
- विनियमित गोदामों को राज्य करेंगे एपीएमसी के रूप में अधिसूचित
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 40 गोदामों को पहले ही कर चुके हैं मंडियों के रूप में अधिसूचित
- ऐसे गोदामों में जिंस रखने वाले किसानों को मिलेगी ई-एनडब्ल्यूआर
- अपनी जिंस की भौतिक डिलिवरी के बजाय किसान कर सकेंगे ऐसी ई-एनडब्ल्यूआर की डिलिवरी
- कर्ज पाने के लिए भी किसान कर सकेंगे इन रसीदों का इस्तेमाल
- अपनी उपज की बिक्री के लिए उचित दामों का कर सकेंगे इंतजार
- 31 दिसंबर, 2019 तक एनईआरएल ने 1.8 लाख से अधिक ई-एनडब्ल्यूआर / ई-डब्ल्यूआर जारी कीं

एनईआरएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी केदार देशपांडे ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार चलते हुए हम पहले ही अपना भंडारगृह ई-नाम के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में हैं। इस एकीकरण से किसानों को डब्ल्यूडीआरए के पंजीकृत वेयरहाउसों में गुणवत्तापूर्ण उपज का भंडारण करके नीलामी में भाग लेने में मदद मिलेगी जो पहले से ही देश भर में अपने वेयरहाउस नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पंजीकृत वेयरहाउस बाजार स्थल बन जाएंगे। यह भारत में वेयरहाउस आधारित बिक्री की शुरुआत होगी। एक दृष्टिकोण के रूप में यह ई-नाम को देशव्यापी रूप से सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ई-एनडब्ल्यूआर तब उपयोगी होगा, जब किसान विनियामक द्वारा विनियमित वेयरहाउस में अपनी उपज रखें और उस वेयरहाउस को उप-मंडी या बाजार स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाए। सरकार पहले ही राज्यों को नए एपीएमसी अधिनियम का पालन करने के लिए कह चुकी है जो वेयरहाउसों को बाजार स्थल के रूप में अधिसूचित करता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 40 से अधिक वेयरहाउसों को बाजार स्थल के रूप में अधिसूचित कर चुके हैं। कम से कम 15 अन्य राज्यों ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को बताया है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं।

> ई-एनडब्ल्यूआर तब उपयोगी होगा, जब किसान विनियामक द्वारा विनियमित वेयरहाउस में अपनी उपज रखें और उस वेयरहाउस को उप-मंडी या बाजार स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाए

ई-नाम मंडियों या कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने वाला राष्ट्रीय नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। इससे किसानों को उन राज्य में अपनी उपज के अधिकतम दाम प्राप्त करने में मदद मिलती है जिनमें वे उपज बेच रहे होते हैं। सामान्य बाजारों में किसानों को उस मंडी या एपीएमसी में प्रचलित दाम मिलते हैं जहां वे अपने उत्पाद पेश करते हैं। जबकि ई-नाम राज्य की सभी मंडियों और सभी राज्यों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ता है, इसलिए अगर किसान इस इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री करते हैं तो उस राज्य की किसी भी मंडी में प्रचलित सबसे अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जिंस डेरिवेटिव एक्सचेंजों पर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिबल वेयरहाउस रसीदों की खरीद बढ़ रही है, लेकिन सरकार ई-नाम प्लेटफॉर्म पर ऐसी वेयरहाउस रसीदों को प्रोत्साहन और इन्हें जारी करने की सुविधा देने के लिए बाजार के सहभागियों के साथ बातचीत कर रही थी। इन रसीदों की उपयोगिता यह है कि बैंकों से पैसा लेने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और भौतिक जिंसों की डिलिवरी के स्थान पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

ई-नाम जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाजार प्लेटफॉर्म पर किसानों को भौतिक रूप में जिंस लाने की जरूरत नहीं होती, अगर उनके पास विनियमित वेयरहाउस में जमा कराई गई वस्तुओं के एवज में जारी रसीदें हों, तो वे ही काफी रहती हैं। जिंसों के बदले किसान एक्सचेंज पर केवल ऐसी रसीदें ही जमा कर देता है। इन रसीदों के आधार पर उसकी वस्तुएं बिक्री के लिए रख दी जाती हैं और उसे बेहतरीन दाम मिल जाते हैं। दूसरी ओर खरीदार को रसीद मिल जाएगी और भंडारगृह किसान की जमा जिंस उस खरीदार को दे देंगे। किसान इन रसीदों का इस्तेमाल इनके एवज में कर्ज लेने के लिए भी कर सकता है और वह अपनी जिंसों की बिक्री के लिए बढ़िया दाम मिलने तक इंतजार भी कर सकता। वह जिंसों को मंडियों में बेचने के दबाव से भी बच सकता है।

इस्पात मांग बढ़ने से कंपनियों का घरेलू बाजार पर जोर

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 5 फरवरी

इस्पात के लिए मांग बढ़ने और लगातार कीमत वृद्धि से कंपनियां फिर से घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं।

इस्पात कंपनियां ने फरवरी में इस्पात की चादरों के दामों में प्रति टन 1,700 से 2,000 रुपये तक का इजाफा किया है। यह लगातार चौथी दाम वृद्धि है। इस इजाफे से पहले घरेलू इस्पात और आयात के बीच दामों का अंतर प्रति टन लगभग 30 डॉलर था।

पिछले कुछेक महीनों के दौरान अंतरराष्ट्रीय दामों में प्रति टन 50 से 100 डॉलर तक के इजाफे और कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से दामों यह वृद्धि हुई है। जेएसडब्ल्यू स्टील के निदेशक (वाणिज्य एवं विपणन) जयंत आचार्य ने कहा कि मांग में सुधार हुआ है और दाम निम्नतम स्तर पर जा चुके हैं।

सितंबर-अक्टूबर में सुस्ती के बाद, नवंबर से कीमतों में सुधार आना शुरू हुआ है। पिछले साल अप्रैल में हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 530 डॉलर प्रति टन के आसपास थीं। सितंबर-अक्टूबर में ये कीमतें घटकर 430 डॉलर प्रति टन पर आ गईं थीं और अब चढ़कर 505 डॉलर के आसपास हैं। घरेलू बाजार के लिए भी कीमतें नवंबर से चढ़ी हैं। पिछले तीन महीनों में ग्राहकों के लिए कीमत वृद्धि लगभग 3,000 रुपये प्रति टन रही है।

हालांकि कंपनियां और विश्लेषक करोना वायरस को लेकर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं जिसकी वजह से चीन से इस धातु की मांग में कमी आई है और दामों पर असर पड़ा है। इस्पात के लंबे उत्पादों के दामों में भी प्रति टन 1,500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है।

इस्पात की जमाखोरी भी कीमत वृद्धि का प्रमुख कारक है। एक अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक के अधिकारी ने कहा, 'इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में मांग में सुधार दिखा है।' इसके परिणामस्वरूप, सभी आपूर्ति श्रृंखलाओं में इन्वेंट्री में कुछ नरमी आई है। उदाहरण के लिए, पिछली तिमाही के दौरान जेएसडब्ल्यू का इन्वेंट्री स्तर 245,000 टन तक घटा है। आचार्य को अगले कुछ महीनों में मांग में और सुधार आने का अनुमान है। मांग में सुधार इस्पात कंपनियों को घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

> इस्पात कंपनियां ने फरवरी में इस्पात की चादरों के दामों में प्रति टन 1,700 से 2,000 रुपये तक का इजाफा किया है। यह लगातार चौथी दाम वृद्धि है

- इस्पात कीमतों में नवंबर से सुधार आना शुरू हुआ है
- जमाखोरी और मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है
- अब तक कंपनियां लगातार तीन बार कीमतें बढ़ा चुकी हैं
- कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार आकर्षक हो गया

आचार्य ने कहा कि जेएसडब्ल्यू का निर्यात जहां दूसरी तिमाही में कुल बिक्री का 31 प्रतिशत था, वहीं तीसरी तिमाही में यह घटकर 24 प्रतिशत रह गया। उन्होंने कहा, 'निर्यात में नरमी चौथी तिमाही में भी संभावित थी, भले ही यह तिमाही मौसमी तौर पर मजबूत समझी जाती थी।'

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयंत रॉय का कहना है कि कीमतों में वृद्धि को देखते हुए कंपनियों द्वारा घरेलू बाजार पर ध्यान बढ़ाना लाजिमी है। इन्वेंट्री स्तर में कमी लाने के लिए इस्पात कंपनियों ने दूसरी तिमाही में निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया था। हालांकि मासिक आधार पर निर्यात में कमी आई है। रॉय ने कहा, 'खासकर इस पर ध्यान रखे जाने की जरूरत होगी कि क्या फरवरी में की गई कीमत वृद्धि बरकरार रहेगी।' मौजूदा समय में, एचआरसी की कीमत लगभग 36,000 रुपये प्रति टन है, यही स्तर अगस्त 2019 में देखने को मिला था। रॉय ने कहा कि तब और मौजूदा समय के बीच एकमात्र अंतर यह रहा कि कोकिंग कोयला कीमतें पिछले साल अगस्त में 200 डॉलर प्रति टन पर थीं और मौजूदा समय में ये 150 डॉलर पर हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 5	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,687.0	-7.0	2,021.9	6.7
Copper	5,652.0	-3.9	6,304.4	2.9
Nickel	12,800.0	-21.2	13,690.0	-20.4
Lead	1,854.5	-14.7	2,106.1	-2.7
Tin	16,155.0	-2.5	17,340.6	-1.1
Zinc	2,217.5	-14.5	2,471.2	-11.3
Gold ($/ounce)	1,553.7*	4.7	1,749.0	3.1
Silver ($/ounce)	17.6*	0.1	19.9	-2.9
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	54.6*	-13.4	58.0	-6.4
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-35.7	1.8	-35.9
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	196.1	8.6	291.4	-5.0
Maize	186.5*	7.3	267.8	-7.2
Sugar	415.5*	19.5	490.3	-0.7
Palm oil	690.0	14.5	1,151.4	19.7
Rubber	1,354.2*	-5.2	1,881.5	5.6
Coffee Robusta	1,276.0*	-2.1	1,811.3	-5.5
Cotton	1,501.4	6.7	1,603.2	-0.7

* As on Feb 5, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.2& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	48.5	35759
Oil and Oilseeds	475.0	70625
Spices	0.1	9
Metal(Feb 04)		
Metal- non ferrous	6637.6	43880
Metal- precious	12142.7	397
Oil and gas(Feb 04)		
Gas	2102.8	49744
Oil	21012.2	3509

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	121.6	139421
Grains	256.5	96845
Oil and Oilseeds	1033.3	449340
Others	115.6	64740
Pulses	84.9	41775
Spices	24.9	21323

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Feb 28)	770.2	3.3
Natural Gas (Feb 25)	133.7	2.0
Copper (Feb 28)	428.6	1.6
Cotton (Feb 28)	19410.0	0.9
Nickel (Feb 28)	946.3	0.9
Mentha Oil (Feb 28)	1189.9	0.8
Losers (* % Change)		
Gold Mini (Feb 05)	40056.0	-1.4
Gold Guinea (Feb 28)	31889.0	-1.4
Gold Petal (Feb 28)	3971.0	-1.3
Crude Oil (Feb 19)	3584.0	-1.2
Gold (Feb 05)	40302.0	-0.9
Silver (Mar 05)	45534.0	-0.8

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Soyabean Indore (Feb 20)	4172.0	2.7
Bajra (Feb 20)	1942.0	2.6
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	864.8	2.1
Guar Seed 10 (Feb 20)	3926.0	1.3
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3900.0	1.1
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1774.0	1.0
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	6946.0	0.9
Losers (* % Change)		
Chana-Bikaner (Mar 20)	3908.0	-1.6
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5946.0	-1.2
Barley Jaipur (Apr 20)	1718.0	-0.9
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4088.0	-0.5
Coriander-Kota (Apr 20)	6361.0	-0.3

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1076.0	5.0
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19410.0	2.3
Gold Ahm (Feb 05)	40302.0	0.6
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	45555.0	0.1
Silver Ahm (Mar 05)	45534.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1189.9	-10.4
Lead Min Mumbai (Feb 28)	145.2	-3.6
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3608.3	-2.8
Nickel Mumbai (Feb 28)	946.3	-2.8
Zinc Mini Mumbai (Feb 28)	171.5	-2.7
Alumini-Mumbai (Feb 28)	135.4	-2.7
Lead Mum (May 29)	147.1	-2.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1942.0	3.5
Bajra-Delhi (Feb 20)	1942.0	1.7
Maize-Sangli (Feb 20)	1907.0	1.5
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3133.0	1.1
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5946.0	0.5
Moong-Merta City (Feb 20)	7697.0	0.5
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1718.0	-20.0
Jeera Unjha (Mar 20)	13830.0	-4.8
Crude Palm Oil Kandl (Feb 28)	719.3	-3.0
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	6946.0	-1.8
Coriander-Kota (Apr 20)	6361.0	-1.2

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	106.....................(106)
Aluminium ingots /kg	144.....................(144)
Brass sheet cutting /kg	320.....................(320)
Brass utensil scraps/kg	305.....................(305)
Copper heavy scrap /kg	416.....................(416)
Copper utensil scraps/kg	392.....................(390)
Copper wire bar /kg	449.....................(449)
Lead ingots /kg	150.....................(151)
Nickel Cathodes /kg	975.....................(975)
Tin slabs /kg	1235..................(1235)
Zinc slabs /kg	176.....................(177)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10236.................(10236)
DCH - 32 /Qtl	11304.................(11248)
Jaydhar /Qtl	9758...................(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11079.................(11023)

Source:Cotton Association of India

Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	837.....................(837)
Castor Comm /10kg	827.....................(827)
Groundnut oil /10kg	1140..................(1140)
Palm oil /10kg	840.....................(840)
Sunflower exp ref /10kg	870.....................(870)
Sunflower oil exp /10kg	830.....................(830)
Soyabean ref / 10kg	855.....................(855)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3602 ....(3382-3602)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	50.72..................(49.61)
Brent Crude (UK)	54.51..................(53.05)
Brent Crude (WTI)	49.61..................(49.61)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.84...................(1.87)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	295.65................(282.35)
Naptha spot /Rs/MT	45170.................(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.................(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.................(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40049.................(40443)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40210.................(40606)
Silver.999/ kg	45510.................(46010)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18777.35	18848.65
Alumini-Mumbai (M)	1 K	140.35	139.10
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1905.00	1910.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1881.10	1875.70
Barley Jaipur (N)	1 Q	2150.00	2147.05
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3717.00	3720.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4020.00	3996.75
Castor Seed-Kadi (N)	X	3995.00	3977.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4075.20	4025.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4293.15	4250.00
Chana-Akola (N)	X	4015.00	3975.00
Coriander-Gondal (N)	X	6250.00	6338.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6400.00	6365.65
Coriander-Kota (N)	1 Q	6468.80	6437.20
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1821.25	1841.90
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1908.40	1904.60
Cotton-Kadi (N)	1 B	18883.60	18979.20
CPO-Kandla (M)	10 K	751.00	766.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	716.70	741.55
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	722.50	740.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	903.30	904.95
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1549.30	1550.50
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3449.20	3455.55
Gold Ahm (M)	10 G	40471.00	40059.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32507.00	32176.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4066.00	4020.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	6999.15	7070.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3900.45	3950.00
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3840.00	3840.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1078.10	1092.40
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	104.75	104.65
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	15200.00	15000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14650.00	14524.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	850.00	850.55
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1014.20	1012.90
Kapas-Rajkot (N)	X	1009.85	1012.30
Lead Mum (M)	1 K	154.00	150.60
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1886.25	1890.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2192.10	2170.00
Maize-Erode (N)	X	1848.65	1830.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2192.10	2170.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2010.00	2025.00
Maize-Sangli (N)	X	1902.00	1877.90
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4700.00	4700.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7677.50	7660.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4334.00	4334.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	968.00	973.20
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3125.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3175.00	3177.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	330.00	328.80
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33400.00	33280.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	837.50	841.25
Rape mustards-Patan (I)	20 K	750.00	760.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1913.75	1910.65
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5347.40	5346.45
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	805.00	820.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	867.20	870.20
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	865.05	866.35
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	869.25	865.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13300.00	13400.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13217.00	13350.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	45996.00	45510.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4148.00	4188.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4090.50	4100.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4242.00	4297.55
Soy Bean-Akola (N)	X	4200.00	4229.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33375.00	33800.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	866.00	868.60
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31300.00	31300.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31400.00	31400.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28460.00	28460.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3275.00	3270.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3419.05	3404.75
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3283.75	3289.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3476.20	3466.65
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3293.55	3283.70
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3162.00	3152.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5908.35	5915.20
Wheat Delhi (N)	1 Q	2205.00	2206.65
Wheat Kota (N)	1 Q	2166.65	2164.55
Wheat New Indore (N)	1 Q	2180.00	2165.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2127.50	2103.75
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2190.00	2180.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5600.00	5575.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5550.00	5500.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	177.35	176.25

* as on Feb 04, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (बुधवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19290, 19440, 19280, 19410	3053	486	27895
Mar 31	19610, 19700, 19540, 19680	867	181	6284
Apr 30	19800, 19920, 19800, 19820	85	17	604
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1779, 1782, 1745, 1774	19720	1607	43020
Mar 20	1784, 1800, 1761, 1792	33720	2504	70590
Apr 20	1814, 1825, 1786, 1817	3830	348	17610
May 20	1842, 1849, 1815, 1837	470	47	4760
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1069.5, 1077, 1068.5, 1076	512	90	972
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1072, 1077.5, 1068, 1075.5	880	471	3441
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	1942, 1942, 1942, 1942	20	1	120
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1715, 1718, 1715, 1718	20	2	2160
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3880, 3944, 3858, 3926	27745	2698	34975
Mar 20	3926, 3988, 3900, 3968	36525	3731	56080
Apr 20	3966, 4016, 3932, 4006	980	148	1710
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3854, 3924, 3840, 3900	5205	621	10695
Mar 20	3868, 3942, 3854, 3922	5670	708	19030
Apr 20	3890, 3960, 3870, 3960	675	85	4510
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	752.7, 772, 752.7, 770.2	33690	2217	44010
Mar 31	748, 763.5, 745, 760.5	23140	1392	21960
Apr 30	742.7, 762, 740, 759.8	3310	253	4400
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1188.8, 1194.5, 1181.1, 1189.9	135.36	287	187.92
Mar 31	1185, 1189, 1179.1, 1184.2	15.48	30	63.72
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4082, 4114, 4063, 4088	13000	1009	9260
Apr 20	4100, 4132, 4070, 4124	15990	1253	15470
May 20	4130, 4151, 4098, 4138	1100	84	3590
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	851, 867, 851, 864.8	21155	2170	32965
Mar 20	838.2, 856, 838.2, 853.4	26025	2630	48810
Apr 20	837, 851, 833.6, 848.8	4600	424	5405
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4080, 4182, 4064, 4172	35930	3771	71470
Mar 20	4080, 4204, 4066, 4184	48970	5490	134865
Apr 20	4090, 4208, 4086, 4192	16470	1671	78770
May 20	4104, 4218, 4104, 4208	1340	214	14155
Jun 19	4230, 4230, 4228, 4230	65	10	225
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	6890, 7000, 6838, 6946	6470	813	13655
Mar 20	6977, 7087, 6916, 7025	9640	1342	49625
Apr 20	7080, 7157, 7014, 7087	430	57	1460
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3971, 3973, 3898, 3908	16080	1212	24810
Apr 20	3973, 3983, 3908, 3914	4950	411	12690
May 20	4013, 4015, 3950, 3964	540	51	4160
Jun 19	4021, 4021, 4010, 4010	20	2	60
Jul 20	4050, 4050, 4050, 4050	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Mar 13	3700, 3700, 3675, 3687.5	0.2	2	4.1
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6360, 6420, 6310, 6361	1640	137	7550
May 20	6420, 6420, 6367, 6370	90	9	740
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13825, 13855, 13710, 13830	432	125	2097
Apr 20	13515, 13645, 13515, 13610	276	76	1671
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6030, 6030, 5936, 5946	540	103	4800
Apr 20	5962, 5962, 5912, 5930	165	28	4340
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	138, 138, 138, 138	1	1	5
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	135.9, 137.1, 135.4, 136.55	7732	5113	4913
Mar 31	136.95, 137.7, 136.3, 137.35	298	253	436
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	429.5, 436.4, 429.5, 435.1	24842.5	8123	11345
Mar 31	433.75, 437, 433.2, 436.25	440	172	1162.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.4, 146.3, 144.8, 145.75	8372	5776	5801
Mar 31	146.1, 146.8, 145.5, 146.35	254	226	563
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	966, 966, 953.1, 960.6	15045	9231	3276
Mar 31	958.6, 961.1, 953.5, 959	148.5	97	174
Zinc MCX(1 K)				
May 29	174.15, 175.7, 174.15, 174.75	4	4	16
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	172, 174, 171.4, 173.45	28467	16920	16517
Mar 31	173, 174.65, 172.15, 174.1	1234	867	2706
Apr 30	173, 174.2, 173, 173.8	4	4	9
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40201, 40280, 40000, 40161	0.01	8	0
Apr 03	40108, 40298, 39900, 39998	7.5	6469	17
Jun 05	40288, 40461, 40071, 40160	0.56	449	5.1
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	31902, 32130, 31565, 32032	0.01	473	0.01
Mar 31	32050, 32175, 31936, 32044	0	65	0
Apr 30	32090, 32090, 32090, 32090	0	1	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	40690, 40700, 40100, 40255	0	22	0
Mar 05	39938, 40228, 39820, 39936	1.03	8989	0.81
Apr 03	40111, 40268, 39890, 39979	0.19	1663	0.24
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	3979, 4000, 3974, 3982	0	1224	0.01
Mar 31	3993, 4020, 3992, 4002	0	360	0
Apr 30	4060, 4060, 4005, 4031	0	4	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45690, 46016, 45356, 45524	356.61	9786	288.12
May 05	46252, 46525, 45932, 46049	3.18	93	23.31
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45638, 46034, 45375, 45546	46.71	33159	31.57
Apr 30	46194, 46560, 45936, 46096	3.82	2954	7
Jun 30	46761, 47030, 46483, 46528	0.03	23	0.16
Aug 31	47646, 47646, 47646, 47646	0	1	0.02
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45722, 46025, 45369, 45532	119.99	19496	51.31
Apr 30	46327, 46550, 45926, 46090	4.59	854	7.48
Jun 30	46660, 46660, 46660, 46660	0.01	1	0.05
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	133.7, 134.8, 130.7, 131.2	75284mb	34639	52926mb
Mar 26	137.1, 137.4, 133.8, 134.2	2948mb	1858	5174mb
Apr 27	141, 141.2, 138.1, 138.3	161mb	119	260mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3590, 3652, 3551, 3639	21907bl	123855	3405bl
Mar 19	3611, 3677, 3579, 3663	692bl	5783	353bl
Apr 20	3640, 3680, 3614, 3661	2bl	19	5bl
सायं सत्र (मंगलवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19170, 19300, 19110, 19270	4800	747	27385
Mar 31	19430, 19560, 19380, 19540	2292	369	6293
Apr 30	19750, 19800, 19700, 19800	497	59	574
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1067, 1071, 1063, 1067	844	136	812
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1063, 1072, 1062.5, 1069	1537	595	3340
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	732, 752, 725.7, 748.3	38600	2695	46520
Mar 31	727, 742.2, 720, 739.7	11060	717	24480
Apr 30	714.1, 734.5, 714.1, 732.7	420	38	2780
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	841.6, 850.6, 836.4, 849	20425	2184	34960
Mar 20	823, 838, 819.4, 836.2	26275	2484	48365
Apr 20	818, 832, 812.6, 829.6	1760	254	5240
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	135.85, 137.15, 134.6, 135.4	16955	11158	5353
Mar 31	137, 137.8, 135.65, 136.3	583	524	473
Apr 30	136.9, 139.5, 136.35, 137.25	7	7	2
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	424.7, 429.8, 424.7, 428.6	43812.5	14111	10835
Mar 31	427.85, 430.85, 427.25, 430.2	835	326	1082.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.95, 146.9, 144.9, 145.2	16063	10946	5124
Mar 31	146.65, 147.2, 145.6, 145.85	380	370	516
Apr 30	149.5, 149.5, 145, 146.85	8	8	-
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	944, 967.8, 942.2, 946.3	32730	19671	2074.5
Mar 31	949, 965.9, 940.6, 944.1	492	304	130.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	173.35, 173.4, 173, 173.3	4	4	15
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	170.8, 173.1, 170.25, 171.45	61289	35467	15723
Mar 31	172.95, 174, 171.05, 172.1	1761	1428	2533
Apr 30	173, 173, 172.5, 172.95	7	4	6
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40408, 40500, 40112, 40302	0.02	19	0.11
Apr 03	40651, 40689, 39927, 39975	14.57	12392	16.87
Jun 05	40866, 40866, 40130, 40166	0.74	647	4.89
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32370, 32370, 31864, 31889	0.01	883	0.01
Mar 31	32265, 32490, 31868, 31903	0	210	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	40618, 40839, 39750, 40056	0.01	67	0.01
Mar 05	40593, 40598, 39880, 39910	2	16766	0.76
Apr 03	40635, 40663, 39921, 39957	0.35	2837	0.23
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4021, 4025, 3963, 3971	0.01	2646	0.01
Mar 31	4037, 4040, 3987, 3991	0	679	0
Apr 30	4078, 4078, 3959, 4020	0	9	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46367, 46367, 45450, 45534	701.04	19530	265.44
May 05	46583, 46753, 46001, 46049	11.97	344	22.38
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46047, 46200, 45480, 45555	88.86	64356	28.13
Apr 30	46688, 46750, 46021, 46122	8.11	5773	6.74
Jun 30	47100, 47100, 46555, 46631	0.04	33	0.15
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46024, 46346, 45476, 45559	270.45	42682	43.83
Apr 30	46641, 46777, 46030, 46114	9.77	1701	7.07
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	130.6, 134.7, 129.4, 133.7	154663mb	72005	44940mb
Mar 26	134.1, 137.6, 133.1, 136.8	4455mb	2849	4583mb
Apr 27	138.7, 141, 137.8, 140.6	353mb	241	221mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3606, 3680, 3572, 3584	56640bl	322061	3156bl
Mar 19	3632, 3704, 3601, 3611	1376bl	11768	349bl
Apr 20	3662, 3736, 3642, 3668	3bl	23	5bl

Name Exchange (Units)

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

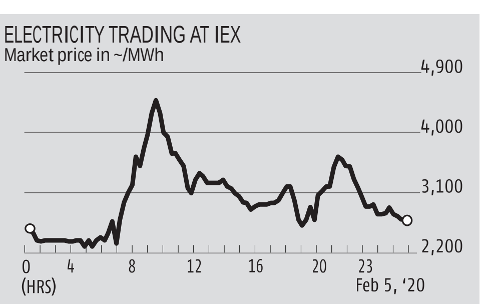

वायरस में सिप्ला की दवा कारगर!

उम्मीद है कि एचआईवी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा कोरोनावायरस संक्रमण करेगी ठीक

सोहिनी दास

चीन से दुनिया भर में फैल रहे जानलेवा कोरोनावायरस के संभावित इलाज के लिए एचआईवी एड्स की दवाइयों के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में सिप्ला जैसी कंपनियों के लिए चीन में अच्छा मौका होगा। कंपनी एचआईवी के इलाज के लिए खास मेल वाली दवा बनाती है जो संभवत: कोरोनावायरस के इलाज में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

सिप्ला के वैश्विक मुख्य वित्तीय अधिकारी केदार उपाध्याय ने कहा, 'अगले हफ्ते तक अगर वैज्ञानिक आंकड़े यह साबित करते हैं कि दो एंटी एचआईवी दवाइयां लोपिनेवीर और राइटोनेवीर का इस्तेमाल कोरोनावायरस के संक्रमण में हो सकता है तब हम इसमें मौका तलाश सकते हैं। हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारत सरकार को भी मुफ्त नमूने दिए हैं।' उनका कहना है कि सिप्ला, ब्रांड लोपिम्यून के तहत जिस दवा का मिश्रण बेचती है उससे एचआईवी वायरल का प्रतिरूप तैयार होने की क्षमता घट जाती हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि वैज्ञानिक तरीके से भी की जानी बाकी है। हालांकि डॉक्टर उस वायरस के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं जिसका प्रसार तेजी से हो रहा है और जिसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। परंपरागत फ्लू की दवाई और केवल टैमिफ्लू से भी वायरस का प्रसार नहीं रोका जा सकता है।

करीब कुछ हफ्ते पहले चीन के डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने पेइचिंग में उन मरीजों में कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जिन्हें एंटी-एचआईवी और एंटी-फ्लू दवा (ओसेलटामिविर) का मिश्रण दिया जा रहा था।

सिप्ला जरूरत पड़ने पर दुनिया भर में दवा की आपूर्ति कर सकती है क्योंकि इसे अमेरिका सहित कई देशों की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य आपात स्थिति होने से दवा की आपूर्ति की मंजूरी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चीन दवा की आपूर्ति को लेकर सिप्ला से पहले से ही जानकारी ले रहा है।

कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है जिससे लोपिम्यून की 1-1.2 करोड़ टैबलेट तैयार की जा सकती है। कंपनी भारत में कई जहों पर ये दवाइयां बनाती है। भारत में इसके 60 टैबलेट की कीमत 2,000 रुपये है। एचआईवी के मरीजों को एक दिन में दो टैबलेट दिया जाता है। ऐसे में एक दिन में इलाज की लागत 60 रुपये प्रतिदिन या एक डॉलर तक है।

चीन के वुहान से लौटे भारतीय नागरिक नई दिल्ली में आईटीबीपी द्वारा तैयार किए गए केंद्र में

एचआईवी की दवा के सीमित इस्तेमाल को मंजूरी

भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के मिश्रण का सीमित इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक शीर्ष स्वास्थ्य शोध संस्थान, भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद (आईसीएमएआर) ने सांस संबंधी दिक्कतों में इस्तेमाल होने वाली दो दवाओं लोपिनाविर और रिटोनाविर के सीमित इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई से आपात मंजूरी मांगी थी।

आईसीएमआर के एक अधिकारी ने बताया, 'हमने अपने अध्ययन में पाया है कि कोरोनावायरस के संक्रमण में यह दवा संभवत: उपयोगी साबित हो सकता है।' इन दवाइयों का इस्तेमाल चीन और थाईलैंड में संक्रमित मरीजों के इलाज में किया गया।

एजेंसियां

हीरा उद्योग को बड़ी चपत

चीन में फैले जानलेवा कोरोनावायरस की वजह से सूरत के हीरा उद्योग को अगले दो महीने में करीब 8,000 करोड़ की चपत लग सकती है। कोरोनावायरस की वजह से हॉन्गकॉन्ग ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। हॉन्गकॉन्ग सूरत के हीरा उद्योग का प्रमुख निर्यात गंतव्य है।

सूरत के हीरा उद्योग कारोबारियों का कहना है कि हॉन्गकॉन्ग उनके लिए प्रमुख व्यापार केंद्र है। लेकिन वहां स्कूल और कॉलेज मार्च के पहले सप्ताह तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोनावायरस के फैलने की वजह से वहां कारोबारी गतिविधियां भी काफी घट गई हैं। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद के क्षेत्रीय चेयरमैन दिनेश नवाडिया ने कहा कि सूरत से हर साल हॉन्गकॉन्ग के लिए 50,000 करोड़ रुपये के पॉलिश हीरों का निर्यात किया जाता है। यह भारत से होने वाले कुल निर्यात का 37 फीसदी तक है। लेकिन अब कोरोनावायरस से हॉन्गकॉन्ग ने एक महीने के अवकाश की घोषणा की है। वहां जिन गुजराती कारोबारियों के कार्यालय हैं, वे वापस लौट रहे हैं।

भाषा

कारोबारी दिग्गज तय करेंगे बीएस विजेताओं के नाम

बीएस संवाददाता

- **आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला आठ सदस्यीय निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हैं।**
- **'सीईओ ऑफ दी इयर' 'कंपनी ऑफ दी इयर' और 'स्टार्टअप ऑफ दी इयर' के लिए चुने जाएंगे विजेता**

देश के उद्योग जगत की जानी-मानी हस्तियों का एक निर्णायक मंडल गुरुवार को मुंबई में बैठक करेगा और वर्ष 2019 के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड के सालाना कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेताओं का चयन करेगा। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला आठ सदस्यीय निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हैं।

निर्णायक मंडल के अन्य सदस्यों में जेएसडब्ल्यू समूह के सज्जन जिंदल, केकेआर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी संजय नैयर, ईवाई इंडिया अध्यक्ष राजीव मेमानी, ओमिड्यार नेटवर्क इंडिया की प्रबंध निदेशक रूपा कुडवा, मैकिंजी ऐंड कंपनी में सीनियर पार्टनर नोशिर काका, सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्रॉफ और बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के प्रबंध निदेशक अमित चंद्रा शामिल हैं।

निर्णायक मंडल बिज़नेस स्टैंडर्ड रिसर्च ब्यूरो द्वारा संकलित नाम तथा डेटा की लंबी सूची में से कॉरपोरेट जगत में बेहतरीन का चयन करेगा। इसमें 'सीईओ ऑफ दी इयर' के अलावा दूसरी श्रेणियों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, लघु तथा मध्यम उद्यम श्रेणी में भी पुरस्कार दिए जाएंगे।

निर्णायक मंडल, 'कंपनी ऑफ दी इयर' और 'स्टार्टअप ऑफ दी इयर' का चयन करने के साथ ही 'लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार की भी घोषणा करेंगे।

निर्णायक मंडल में देश के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को शामिल किया गया है। सीमेंट से लेकर वित्त जैसे विविध क्षेत्रों को चलाने का अनुभव रखने वाले बिड़ला को एक ऐसा दक्ष उद्योगपति भी माना जाता है जिन्होंने विभिन्न रणनीतियों के बलबूते समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जिंदल ने भारतीय स्टील उद्योग पर दांव लगाया और जेएसडब्ल्यू स्टील को पहले पायदान पर पहुंचा दिया। इस उपलब्धि के लिए जिंदल को बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 2017 में 'सीईओ ऑफ दी इयर' के पुरस्कार से नवाजा गया था।

नोशिर काका ने वर्ष 2011-2016 तक प्रबंध निदेशक के तौर पर मैकिंजी इंडिया का नेतृत्व किया और कंपनी की वैश्विक आउटसोर्सिंग एवं ऑफशोरिंग कार्यों तथा बिजनेस टेक्नोलॉजी ऑफिस की स्थापना देश में की। अब वह वैश्विक स्तर पर मैकिंजी एनालाइटिक्स प्रैक्टिस की सह-प्रमुख हैं। मेमानी 1980 के दशक में ईवाई से जुड़े और कंपनी के भारतीय अध्यक्ष पद तक पहुंचे। इसके अलावा वह ईवाई के वैश्विक कार्यकारी बोर्ड के सदस्य तथा ईवाई ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं।

वर्ष 2009 से ही केकेआर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी पद पर रहे नैयर देश में कई अहम प्राइवेट इक्विटी सौदों में शामिल रहे हैं। केकेआर से पहले उन्होंने सिटीबैंक इंडिया का नेतृत्व भी किया है। क्रिसिल की पूर्व मुख्य कार्याधिकारी कुडवा कई प्रमुख भारतीय कंपनियों तथा आईआईएम अहमदाबाद के बोर्ड में शामिल हैं। श्रॉफ मुंबई की सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर हैं और एक शीर्ष स्तर के वकील के तौर पर भारतीय कंपनियों के लिए उनका एक व्यापक नजरिया हैं।

चंद्रा ने साल 2008 में बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी इंडिया कार्यालय की स्थापना की थी और वह इससे पहले डीएसपी मेरिल लिंच के प्रबंध निदेशक थे।

जहाज तक फैला कोरोनावायरस का संक्रमण

बुधवार को दो जहाज के हजारों यात्रियों और चालक दल को अलग रखा गया क्योंकि कोरोनावायरस की वजह से मरने वालों की तादाद लगभग 500 हो गई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि मंगलवार को वायरस के प्रकोप से 65 और लोग मर गए। चीन के हुबेई प्रांत के मुख्य शहर वुहान में दिसंबर में वायरस का संक्रमण फैलने की शुरुआत हुई थी। चीन से बाहर दो लोगों की मौत हुई है और इन दोनों व्यक्तियों ने वुहान की यात्रा की थी। पिछले हफ्ते फिलीपींस में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि मंगलवार को एक 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत हॉन्गकॉन्ग में हो गई।

चीन में संक्रमण के 3,887 नए मामले की पुष्टि हुई है और इस तरह कुल संक्रमित लोगों की तादाद 24,324 हो गई। कोरोनावायरस की वजह से दो दर्जन विमानन कंपनियों ने अपनी हवाई सेवा चीन के लिए बाधित कर दी है। साथ ही अमेरिका सहित कई देशों ने चीन से आए लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इस हफ्ते संक्रमण जहाजों तक फैल गया।

जापान के एक तट पर मौजूद जहाज में 3,700 लोग कम से कम दो हफ्ते से मौजूद हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को जहाज पर 10 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की। डायमंड प्रिंसेज क्रूज पर सवार लोगों ने उन अधिकारियों की मास्क और गाउन पहने ऑनलाइन तस्वीरें पोस्ट कीं जो स्वास्थ्य जांच कर रहे थे। एक ब्रिटिश यात्री डेविड अबेल ने अपने केबिन में शूट किए गए एक वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट किया जिसमें उसने कहा कि हालात ठीक नहीं हैं।

हॉन्गकॉन्ग ने में 3,600 यात्रियों और चालक दल को जांच के बाद जहाज में ही रहने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद तीन लोग संक्रमित पाए गए। हॉन्गकॉन्ग के कैथी पैसिफिक एयरवेज ने अपने 27,000 कर्मचारियों को तीन हफ्ते की बिना भुगतान वाली छुट्टी लेने के लिए कहा है। कंपनी ने कहा कि 2009 के वित्तीय संकट के दौरान स्थिति जितनी गंभीर थी अब भी वैसे ही हालात हैं। चीन में कई फैक्टरियां बंद हैं, कई शहरों की पूरी तरह नाकेबंदी की गई है और यात्रा के सभी संपर्क खत्म हो चुके हैं। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति शृंखला के बाधित होने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि बुधवार को एशियाई शेयरों के प्रदर्शन में स्थिरता दिखी।

हुंडई मोटर ने दक्षिण कोरिया में अपना उत्पादन रोक दिया है क्योंकि कलपुर्जों की आपूर्ति में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। वैश्विक कार निर्माताओं ने पहले ही सरकार के निर्देश के मुताबिक चीन में अपनी फैक्टरियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं।

एजेंसियां

समिति की सिफारिशें वित्त आयोग में शामिल!

पृष्ठ-1 का शेष

समिति अपनी रिपोर्ट 15वें वित्त आयोग को सौंपेगी। आयोग अपनी दूसरी रिपोर्ट में इन सिफारिशों को शामिल कर सकता है। आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है और वह इस साल अक्टूबर में अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप सकता है। वह वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सिफारिशें सौंपेगा। सिंह ने कहा, 'समिति इस बात पर विचार करेगी कि हम अपने कार्यक्षेत्र के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं।' प्रस्तावित समिति और 15वां वित्त आयोग अनुच्छेद 293 (3) के ढांचे पर विचार कर सकते हैं। इसके मुताबिक अगर केंद्र का राज्य पर ऋण बकाया है तो राज्य केंद्र की सहमति के बिना ऋण नहीं जुटा सकता है।

सिंह ने कहा, मैंने एफआरबीएम समिति में इन मुद्दे पर चर्चा नहीं की लेकिन यह मोटे तौर पर केंद्र की वित्तीय स्थिति पर ही केंद्रित रही। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह एफआरबीएम समिति में अपने पुराने सहयोगियों को इस समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे, इस पर सिंह ने कहा, 'रथिन रॉय दिल्ली में हैं जबकि अरविंद सुब्रमण्यन विदेश में हैं लेकिन राजकोषीय मजबूती पर उनके अपने विचार हैं। मैं इस बारे में उर्जित पटेल और साजिद चेनॉय तथा प्राची मिश्रा जैसे विशेषज्ञों के विचार भी जानना चाहूंगा।' एफआरबीएम समिति में सिंह के अलावा पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस, पटेल, सुब्रमण्यन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रॉय शामिल थे। समिति ने 2017-18 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी थी।

योगी सरकार ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

बीएस